@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

'मध्य प्रदेश में कोरोना काल में कई गरीब हितैषी योजनायें चलाई गईं'

वर्ष-16, अंक-14 16-31 जुलाई, 2021 (पाक्षिक) ₹20

मोदी सरकार 2.0 का मंत्रिपरिषद विस्तार

हम एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम करना जारी रखेंगे: प्रधानमंत्री

पिरड़ी, कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और पौधारोपण किया

रोहतांग (हिमाचल प्रदेश) में अटल सुरंग का दौरा करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

लेह में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायु सेना के जवानों के साथ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

नई दिल्ली में अखिल सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, कश्मीर के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार

केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार सात जुलाई को संपन्न हुआ। 43 नये चेहरे सरकार का हिस्सा बने। सात राज्यमंत्रियों को पदोन्नत कर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। कुल 15 सदस्यों को कैबिनेट मंत्री और 28 को राज्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। आठ नए चेहरों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया...

11 पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ

श्री पुष्कर सिंह धामी ने चार जुलाई, 2021 को देहरादून में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के...

12 कोरोना काल में शिवराजजी के नेतृत्व में कई गरीब हितैषी योजनायें चलाई गईं: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय...

15 भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 28 जून, 2021 को...

21 'अयोध्या को हमारी बेहतरीन परंपराओं और विकास के सर्वोत्तम परिवर्तन को प्रकट करना चाहिए'

गत 26 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने...

वैचारिकी

चिति / **दीनदयाल उपाध्याय** 18

श्रद्धांजलि

नहीं रहे भाजपा के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी 20

लेख

तानाशाही मानसिकता से उपजा था आपातकाल / **अमित शाह** 22

स्वामी विवेकानंद की राष्ट्र-निर्माण संबंधी संकल्पना एवं उसका मार्ग / **तरुण चुघ** 24

जनसंख्या वृद्धिः समस्या एवं समाधान / **शिवप्रकाश** 26

मन की बात

जल संरक्षण देश सेवा का ही एक रूप हैः नरेन्द्र मोदी 32

अन्य

भाजपा, हरियाणा एवं बिहार प्रदेश कार्यसमिति बैठक 13

वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 95 अरब डॉलर का सर्वाधिक निर्यात 16

जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआः नरेन्द्र मोदी 17

कोविड टीकाकरण को गति देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की 300 वैज्ञानिकों, शिक्षकों ने की सराहना 28

प्रधानमंत्री द्वारा टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा 29

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की भारी जीत 31

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

उत्तर प्रदेश ने पिछले चार वर्षों के दौरान निवेश बढ़ाने और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को सुधारने में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि छोटे शहर और ग्रामीण इलाके भी इन उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं।

जगत प्रकाश नड्डा

पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा महिलाओं के खिलाफ हुई है, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में! अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो हम किस तरह के शासन के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं? हम सभी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हुए ममता बनर्जी की तानाशाही मानसिकता को नेस्तनाबूद करेंगे।

अमित शाह

डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी की दूरदर्शी सोच व भारत को डिजिटल क्षेत्र में अग्रणी बनाने के संकल्प का परिणाम है। दशकों तक जिन गांवों में बिजली व साफ पानी नहीं पहुंचा था, आज मोदीजी के डिजिटल इंडिया के विजन से 6 साल में वो गांव ऑप्टिकल फाइबर से भी जुड़ चुके हैं।

राजनाथ सिंह

पिछले सात वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर मोदीजी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने बड़े प्रतिबद्ध तरीक़े से काम किया है और सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़े हैं।

बी.एल. संतोष

कोविड प्रभावित क्षेत्र के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50000 करोड़ रुपये और अन्य क्षेत्र के लिए 60000 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

नितिन गडकरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में कैबिनेट ने कोरोना से लड़ने के लिए 23,123 करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को मंजूर किया है। इससे कोरोना की अगली लहर से पहले हमारी तैयारी को और बल मिलेगा।

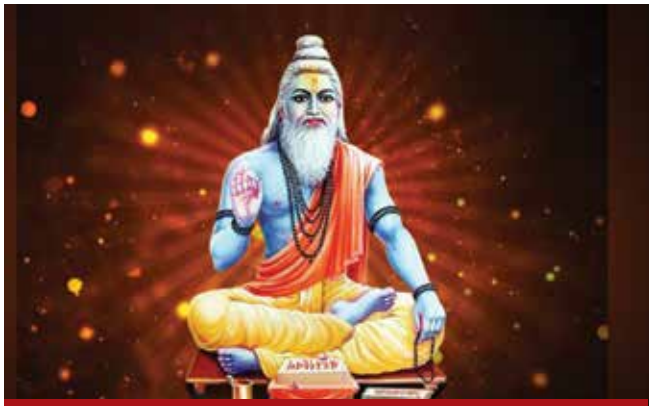

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
गुरू पूर्णिमा (24 जुलाई)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

नई ऊर्जा, उत्साह एवं विश्वास का संचार

मोदी सरकार- 2.0 मंत्रिपरिषद विस्तार से पूरे राष्ट्र में निस्संदेह नई ऊर्जा, उत्साह एवं विश्वास का संचार हुआ है। मोदी सरकार- 2.0 मंत्रिपरिषद में 43 नए चेहरे के शामिल होने से कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से लड़ने के नए संकल्प के साथ देश पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। इस समावेशी मंत्रिपरिषद में 2 कैबिनेट मंत्रियों समेत 11 महिला मंत्रियों का शामिल होना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की शासन में 'नारी शक्ति' की भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। एक ओर जहां मंत्रिपरिषद की औसत आयु 58 वर्ष है, दूसरी ओर छह कैबिनेट मंत्री समेत 14 मंत्री 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे मंत्रिपरिषद में 13 अधिवक्ता, छह डॉक्टर, पांच इंजीनियर, सात प्रशासनिक अधिकारी, सात पीएचडी एवं तीन एमबीए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई एवं सुदृढ़ नेतृत्व में यह युवा, समावेशी एवं 'नारी शक्ति' से युक्त मंत्रिपरिषद पूरे देश को अवश्य नई ऊंचाइयां देगा।

एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 23,123 करोड़ रुपए का 'भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली, चरण-2'' को स्वीकृति दे दी है। इस स्वास्थ्य अवसंरचना का तेजी से विकास होगा तथा बाल चिकित्सा के साथ-साथ बचाव, शुरुआती रोकथाम एवं स्वास्थ्य प्रबंधन व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इससे देश कोविड-19 या अन्य महामारी से उभरने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए और भी अधिक मजबूती से तैयार होगा। मोदी सरकार किसानों की आय दुगुनी करने के लिए शुरू से ही प्रतिबद्ध है। इस दिशा में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, कैबिनेट ने कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत वित्तीय नियमों में आवश्यक परिवर्तन कर कृषि क्षेत्र में भारी निवेश के द्वार खोल दिए हैं जिसका सबसे अधिक लाभ सीमांत किसानों को मिलेगा। इससे उपज के बाद के प्रबंधन के लिए व्यापक 'इकोसिस्टम' का निर्माण संभव हो सकेगा।

विश्व का सबसे बड़ा एवं तेज गति से चल रहा निःशुल्क टीकाकरण अभियान हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब जबकि टीकाकरण अभियान के 175 दिन पूरे हो गए हैं, 9 जुलाई, 2021 तक 37 करोड़ टीका लगाया जा चुका है

विश्व का सबसे बड़ा एवं तेज गति से चल रहा निःशुल्क टीकाकरण अभियान हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब जबकि टीकाकरण अभियान के 175 दिन पूरे हो गए हैं, 9 जुलाई, 2021 तक 37 करोड़ टीका लगाया जा चुका है। यह अभियान दिनोंदिन तेज होता जा रहा है तथा आठ प्रदेशों में 18-44 आयु वर्ग के 50 लाख से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। ध्यान देने योग्य है कि मोदी सरकार पूर्व में 45+ आयु वर्ग के लोगों को टीका देने का दायित्व निर्वहन कर रही थी तथा 18-44 आयु वर्ग के टीके का दायित्व प्रदेशों के पास था। जहां भाजपा शासित राज्य सरकारें लोगों को निःशुल्क टीका देने को प्रतिबद्ध थीं, वहीं कुछ अन्य राज्य टीका उपलब्ध करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे थे। परिणामतः, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18-44 आयुवर्ग के भी टीके का दायित्व अपने कंधों पर ले लिया और 21 जून 2021 से इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। अब देश के हर कोने में लोग आश्वस्त हैं कि सबका टीकाकरण होगा और निःशुल्क होगा।

पूरा राष्ट्र कोविड-19 महामारी से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में एकजुट होकर विभिन्न मोर्चों पर लड़ रहा है। एक ओर जहां इस महामारी ने विश्व के अनेक विकसित देशों को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है, भारत में जन-जन ने अदम्य धैर्य एवं साहस का परिचय देते हुए इसे नियंत्रित करने के प्रयास किए हैं। ऐसे कठिन दौर में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के एक वर्ग ने देश में भय एवं आशंका के वातावरण का निर्माण करने का कुप्रयास किया। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस के लिए लोगों के जीवन से ऊपर राजनीति रही है। आज जबकि पूरा राष्ट्र महामारी से एकजुट होकर लड़ रहा है, मंत्रिपरिषद विस्तार सरकार को नई गतिशीलता, निश्चित दिशा एवं ऊर्जा देगा। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार

जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे: नरेन्द्र मोदी

केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार सात जुलाई को संपन्न हुआ। 43 नये चेहरे सरकार का हिस्सा बने। सात राज्यमंत्रियों को पदोन्नत कर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। कुल 15 सदस्यों को कैबिनेट मंत्री और 28 को राज्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। आठ नए चेहरों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया।

जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली उनमें 26 लोकसभा के सदस्य हैं जबकि आठ राज्यसभा से हैं। सात महिलाओं को इस मंत्रिपरिषद विस्तार में जगह दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी को मिलाकर अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिला मंत्रियों की कुल संख्या नौ हो गई है। प्रधानमंत्री ने इस विस्तार में त्रिपुरा और मणिपुर जैसे राज्यों को भी जगह दी है।

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए सभी 43 सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू, लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद थे।

कुल 12 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित 78 हो गई। प्रधानमंत्री के रूप में मई, 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल आरंभ करने के बाद श्री मोदी ने पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद विस्तार किया है।

कैबिनेट मंत्री के रूप में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य श्री भूपेंद्र यादव, असम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद श्री वीरेंद्र कुमार, ओडिशा से भाजपा के राज्यसभा सदस्य श्री अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य श्री नारायण राणे, जनता दल यूनाईटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी के श्री पशुपति कुमार पारस ने शपथ ली।

इनके अलावा सर्वश्री किरेन रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह

मैं उन सभी सहकर्मियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की और उन्हें मंत्री के रूप में उनके बेहतर कार्यकाल की शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये काम जारी रखेंगे तथा मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे।

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले सभी नवनियुक्त मंत्रियों को हार्दिक बधाई! मुझे विश्वास है कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आप सभी देश के विकास को गति देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे एवं 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को साकार करेंगे।

- जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

पुरी और मनसुख भाई मांडविया ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इन चारों नेताओं को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया।

श्री रिजिजू इससे पहले युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) थे और श्री सिंह पहले विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) थे, जबकि श्री पुरी आवासन तथा शहरी विकास और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) थे। श्री मांडविया बंदरगाह, पोत और जलमार्ग परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) थे।

जिन राज्यमंत्रियों को पदोन्नत करके सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया गया उनमें श्री परशोत्तम रूपाला, श्री जी. किशन रेड्डी और श्री अनुराग सिंह ठाकुर शामिल हैं। श्री रूपाला इससे पहले कृषि राज्यमंत्री थे जबकि श्री रेड्डी गृह राज्यमंत्री और श्री ठाकुर वित्त राज्यमंत्री थे।

राज्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से भाजपा के सांसद श्री पंकज चौधरी, अपना दल (एस) की श्रीमती अनुप्रिया पटेल, आगरा के सांसद श्री एस. पी. सिंह बघेल, कर्नाटक से भाजपा के राज्यसभा सदस्य श्री राजीव चंद्रशेखर, कर्नाटक के ही उडुपी चिकमंगलूर से सांसद सुश्री शोभा करंदलाजे, उत्तर प्रदेश के जालौन से पांचवीं बार के सांसद श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, गुजरात के सूरत की सांसद श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, नयी दिल्ली की सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी, झारखंड के कोडरमा की सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, कर्नाटक के चित्रदुर्ग के सांसद श्री ए. नारायणस्वामी, उत्तर प्रदेश के मोहनलाल गंज से सांसद श्री कौशल किशोर, उत्तराखंड के नैनीताल-ऊधमसिंह नगर से सांसद श्री अजय भट्ट, उत्तर प्रदेश के ही खीरी से सांसद श्री अजय मिश्रा, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य श्री बी. एल. वर्मा, गुजरात के खेड़ा से सांसद श्री देवुसिंह चौहान, कर्नाटक के बीदर से सांसद श्री भगवंत खूबा, महाराष्ट्र के भिवंडी से सांसद श्री कपिल पाटिल, पश्चिम त्रिपुरा की सांसद सुश्री प्रतिमा भौमिक, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से सांसद श्री सुभाष सरकार, महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य श्री भागवत कराड, मणिपुर के सांसद श्री राजकुमार रंजन सिंह, महाराष्ट्र के ही दिन्डोरी से सांसद डॉ. भारती प्रवीण पवार, ओडिशा के मयूरभंज से सांसद श्री विश्वेश्वर टुडु, पश्चिम बंगाल के बनगांव के सांसद श्री शांतनु ठाकुर, गुजरात के सुरेंद्रनगर से सांसद श्री मुंजापरा महेंद्र भाई, पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर से सांसद श्री जॉन बारला, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष श्री एल. मुरुगन और पश्चिम बंगाल के कूचबिहार से सांसद श्री निसिथ प्रमाणिक शामिल हैं।

नवगठित सहकारिता मंत्रालय का प्रभार केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को दिया गया। श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और श्री एस. जयशंकर पूर्व की भांति अपने-अपने मंत्रालयों का कार्यभार देखते रहेंगे। श्री सिंधिया को नागर विमानन मंत्रालय, श्री नारायण राणे को लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमिता मंत्रालय तथा श्री सर्बानंद सोनोवाल को पोत, जहाजरानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। श्री वीरेन्द्र सिंह

शेष पृष्ठ 10 पर...

श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री और इन मंत्रालयों का प्रभारः कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री

श्री राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री

श्री अमित शाह
गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री

श्री नितिन जयराम गडकरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

श्रीमती निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री

श्री नरेंद्र सिंह तोमर
कृषि और किसान कल्याण मंत्री

डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर
विदेश मंत्री

श्री अर्जुन मुंडा
जनजातीय मामलों के मंत्री

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी
महिला एवं बाल विकास मंत्री

श्री पीयूष गोयल
वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री

श्री धर्मेंद्र प्रधान
शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री

श्री प्रल्हाद जोशी
संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री

श्री नारायण तातु राणे
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

श्री सर्बानंद सोनोवाल
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री

श्री मुख्तार अब्बास नकवी
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री

डॉ. वीरेंद्र कुमार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

श्री गिरिराज सिंह
ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया
नागरिक उड्डयन मंत्री

श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह
इस्पात मंत्री

श्री अश्विनी वैष्णव
रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

श्री पशुपति कुमार पारस
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत
जल शक्ति मंत्री

श्री किरेन रिजिजू
कानून और न्याय मंत्री

श्री राज कुमार सिंह
विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

श्री हरदीप सिंह पुरी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री

श्री मनसुख मंडाविया
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन व उर्वरक मंत्री

श्री भूपेंद्र यादव
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री

श्री महेंद्र नाथ पांडेय
भारी उद्योग मंत्री

श्री परशोत्तम रूपाला
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

श्री जी. किशन रेड्डी
संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

श्री अनुराग सिंह ठाकुर
सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवा मामले और खेल मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

राव इंद्रजीत सिंह
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री

डॉ. जितेंद्र सिंह
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री श्रीपद येसो नाइक
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री प्रहलाद सिंह पटेल
जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री अश्विनी कुमार चौबे
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री अर्जुन राम मेघवाल
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री

जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री कृष्ण पाल
विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री रामदास आठवले
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री

साध्वी निरंजन ज्योति
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

डॉ. संजीव कुमार बालियान
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री नित्यानंद राय
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री पंकज चौधरी
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री राजीव चंद्रशेखर
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री

सुश्री शोभा करंदलाजे
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री वी. मुरलीधरन
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्रीमती मीनाक्षी लेखी
विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री सोम प्रकाश
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता
जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री रामेश्वर तेली
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और
श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री कैलाश चौधरी
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री ए. नारायणस्वामी
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री कौशल किशोर
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री अजय भट्ट
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री बी. एल. वर्मा
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री अजय कुमार
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री देवुसिंह चौहान
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री भगवंत खुबा
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री और
रसायन व उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल
पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री

सुश्री प्रतिमा भौमिक
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री

डॉ. सुभाष सरकार
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

डॉ. भागवत किशनराव कराड
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

डॉ. राजकुमार रंजन सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

डॉ. भारती प्रवीण पवार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री बिश्वेश्वर टुडू
जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री और
जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री शांतनु ठाकुर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री

डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई
महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और
आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री जॉन बारला
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री

डॉ. एल. मुरुगन
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री निसिथ प्रमाणिक
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और
युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री

पृष्ठ 7 का शेष...

को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का प्रभार दिया गया। वहीं, जदयू अध्यक्ष श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय दिया गया। श्री अश्विनी वैष्णव को रेल, संचार तथा इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया, जबकि श्री पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का प्रभार दिया गया। श्री किरण रिजिजू को विधि एवं न्याय मंत्रालय, श्री भूपेन्द्र यादव को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। श्री धर्मेन्द्र प्रधान को शिक्षा तथा कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय, श्री हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम, शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय, श्री अनुराग ठाकुर को सूचना प्रसारण मंत्रालय और युवा एवं खेल मंत्रालय का प्रभार दिया गया। ■

भाजपा ओबीसी मोर्चा ने जताया आभार

मोदी सरकार 2.0 मंत्रिपरिषद विस्तार में 35 प्रतिशत मंत्रियों को ओबीसी वर्ग (पिछड़ा वर्ग) से प्रतिनिधित्व मिला। 27 ओबीसी मंत्रियों को शामिल किया गया जो आज तक सबसे अधिक प्रतिनिधित्व साबित हुआ, जिसमें 5 कैबिनेट मंत्री एवं 21 राज्यमंत्री एवं एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में शामिल हुए। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के. लक्ष्मण ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में ओबीसी वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व देने पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री पुष्कर सिंह धामी ने चार जुलाई, 2021 को देहरादून में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। श्री धामी उत्तराखंड में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 11 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें सर्वश्री सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंसीधर भगत, यशपाल आर्या, बिशन सिंह चौपाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, सुश्री रेखा आर्या और स्वामी यतीश्वरानंद शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। उन्होंने शपथ लेने वाले अन्य मंत्रियों को भी बधाई दी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पुष्कर सिंह धामी और शपथ लेने वाले अन्य सभी मंत्रियों को बधाई। इस टीम को उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि की दिशा में काम करने के लिए शुभकामनाएं।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने श्री धामी को बधाई देते हुए ट्वीट कर कहा कि श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी व प्रदेश में प्रगति के नये मापदंड स्थापित होंगे।

शपथ लेने के बाद श्री धामी ने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर बनाए रखने के लिए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मूल मंत्र पर राज्य सरकार काम करेगी। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है।

उन्होंने कहा कि मैं युवाओं के बीच काम कर रहा हूं और मैं उनके मुद्दों को अच्छी तरह समझता हूं। कोविड ने उनकी आजीविका को प्रभावित किया है। हम उनके लिए स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और राज्य में रिक्त पदों पर युवाओं को नियुक्त करने का प्रयास करेंगे। ■

जीवन परिचय

पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री
आयु: 45 वर्ष

राजनीतिक यात्रा

1990: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए
2001- 2002: तत्कालीन मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के विशेष कार्य अधिकारी
2002-2008: भाजपा के उत्तराखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया
2012: खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित; 2017 में फिर से चुने गए
2016: प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष नियुक्त
4 जुलाई, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

कोरोना काल में शिवराजजी के नेतृत्व में कई गरीब हितैषी योजनायें चलाई गईं: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 24 जून, 2021 को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में जारी विकास यात्रा को मध्य प्रदेश की विकास गाथा पर विस्तार से चर्चा करते हुए पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को कई निर्देश भी दिए। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा उपस्थित थे। दिल्ली में मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य सभा में नेता श्री थावरचंद गहलोत, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर, केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल, सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश और मध्य प्रदेश के प्रभारी श्री मुरलीधर राव के साथ साथ कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने मध्य प्रदेश कार्यसमिति गठित होने के बाद पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीन कार्यकाल तक, लगभग 15 सालों तक सरकार चलाई है और इस दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश में विकास की नई लकीर खींची है। हालांकि बीच में डेढ़ साल का एक ऐसा कालखंड आया जहां राज्य की जनता को एक दूसरी और भयावह तसवीर देखने को मिली। कांग्रेस की सरकारें कैसे चलती हैं, ये लोग भूल गए थे। वर्षों बाद उन्हें एक बार फिर समझ में आया कि कांग्रेस और भाजपा की सरकार में रात-दिन, अंधेरा-उजाला और अमावस्या-पूर्णिमा का अंतर है। इन डेढ़ सालों में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार के रूप में वसूली, ट्रांसफर और भ्रष्टाचार वाली सरकार देखी। इस दौरान विकास के सारे कार्य रुक गए, कई प्रोजेक्ट रोक दिए गए, मिशन कमीशन में बदल दिए गए। कांग्रेस की इस डेढ़ वर्ष की सरकार ने हर वर्ग को धोखे में रखा और सिवाय कन्फ्यूजन के कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने और जनता के सहयोग से एक बार पुनः प्रदेश में श्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।

28,000 करोड़ रुपये वेलफेयर योजनाओं के तहत पिछले एक वर्ष में खर्च किये गए हैं

कांग्रेस पर हमला करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का इतना पतन हो गया है कि वह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते करते देश की आलोचना शुरू कर देती है। कमलनाथ जी ने कहा कि भारत महान कहां है, भारत तो बदनाम है। अरे, आपको भाजपा का विरोध करना है तो कीजिये लेकिन देश को क्यों बदनाम करते हो? दिग्विजय सिंह तो क्लब हाउस पर धारा 370 और 35A के बारे में क्या सोचते हैं, ये तो पूरे देश ने सुना है। जिस धारा 370 और 35A को कांग्रेस हटा नहीं पाई, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की रणनीति ने धाराशायी कर दिया और जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। आज जम्मू-कश्मीर पर प्रधानमंत्री जी बैठक कर रहे हैं और वहां विकास की धारा बहनी शुरू हो गई है लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसी नेताओं को इसका दुःख हो रहा है।

श्री नड्डा ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रवासी मजदूर सहायता योजना के तहत 1.55 लाख कामगारों के एकाउंट में 15.50 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। श्रम सिद्धि अभियान के तहत 32 करोड़ मेन डेज क्रियेट किया गया जिसमें 60 लाख जॉब कार्ड होल्डर्स को काम दिया गया। रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से लगभग 45,000 स्किल्ड और माइग्रेंट लेबरर्स को गवर्नमेंट में रोजगार दिया गया है। चम्बल एक्सप्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे का काम शुरू हो रहा है। 28,000 करोड़ रुपये वेलफेयर योजनाओं के तहत पिछले एक वर्ष में खर्च किये गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में शिवराजजी के नेतृत्व में कई गरीब हितैषी योजनायें चलाई गईं। गरीब कल्याण अन्न उत्सव के जरिये लगभग 37 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा गया। पोषण उत्सव के तहत आंगनबाड़ी में 8 लाख बच्चों को दूध का वितरण किया गया। संबल उत्सव के जरिये लोगों की मदद की गई। फारेस्ट राइट्स के तहत आदिवासी भाइयों के लिए काम हुआ है। ■

'मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में राज्य में विकास की लहर चली है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 24 जून, 2021 को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया।

इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश प्रभारी श्री विनोद तावड़े, सह प्रभारी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री श्री रतन लाल कटारिया, श्री संदीप जोशी, प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज, प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर, प्रदेश के खेल मंत्री श्री संदीप सिंह, प्रदेश महामंत्री श्री वेदपाल जी और संगठन मंत्री श्री रवींद्र राजू सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित थे।

आज लगभग 551 सरकारी योजनाओं का लाभ सरल केन्द्रों पर बिना किसी भ्रष्टाचार के सरलता से उपलब्ध है

श्री नड्डा ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा ने विकास की जो लहर चली है और विकास के जो बड़े-बड़े कार्य हुए हैं, उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। हरियाणा में मेरा परिवार, मेरी पहचान और मेरा पानी, मेरी विरासत जैसी योजनाओं ने न केवल आर्थिक और सामाजिक रूप से निचले पायदान पर खड़े व्यक्तियों का सशक्तिकरण किया, बल्कि जल के संरक्षण और संवर्धन पर भी जोर दिया। प्रदेश के हर गांव में अटल सेवा केंद्र प्रारंभ हुआ। आज लगभग 551 सरकारी योजनाओं का लाभ सरल केन्द्रों पर बिना किसी भ्रष्टाचार के सरलता से उपलब्ध है। पिछले सात वर्षों में लगभग 4,000 करोड़ रुपये के 165 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और लगभग 292 नए प्रोजेक्ट लांच हुए हैं। लगभग 266 करोड़ रुपये की परिवार समृद्धि योजना से हरियाणा में लगभग 12 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। कोरोना प्रभावित बच्चों के लिए कई योजनाओं का सूत्रपात किया गया है। कोविड से मृत्यु पर हर बीपीएल परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा प्रदेश सरकार की ओर से दिया जा रहा है। प्रदेश में किसानों और आढ़तियों को 10 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर दिया गया है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के माध्यम से उन परिवारों को 6,000 रुपये की विशेष आर्थिक मदद दी जा रही है जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है। ■

'राजग सरकार में बिहार लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 27 जून, 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार प्रदेश के प्रभारी श्री भूपेन्द्र यादव, केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, श्री नित्यानंद राय और श्री अश्विनी चौबे, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद और श्रीमती रेणु देवी, बिहार प्रदेश संगठन महामंत्री श्री नागेंद्रजी, बिहार सरकार में भाजपा के मंत्रीगण, विधायक गण, जिला भाजपा अध्यक्ष और कार्यसमिति के सदस्य वर्चुअली उपस्थित थे।

30 अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं

श्री नड्डा ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आगे बढ़कर 130 करोड़ देशवासियों को साथ लेते हुए देश का नेतृत्व किया। मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत ने केवल एक साल में अभूतपूर्व प्रगति की। आज देश में 2500 कोविड टेस्टिंग लैब्स हैं, रोजाना 25 लाख की टेस्टिंग कैपिसिटी है। पीपीई किट्स, फेस मास्क, सेनिटाइजर, वेंटिलेटर्स, कोविड बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स और आईसीयू बेड्स की आज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार ने भी कोविड मैनेजमेंट को अच्छे ढंग से निभाया है। बिहार में आज लगभग 28,260 कोविड बेड्स, 16,800 ऑक्सीजन बेड्स और 1582 आईसीयू बेड्स हैं। डीबीटी के माध्यम से जरूरतमंदों को बिहार की एनडीए सरकार ने 6,000 रुपये की आर्थिक मदद की है।

श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत से अब तक लगभग 1.80 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं और इस पर अब तक लगभग 23 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। बिहार में भी इस योजना के तहत लगभग 2.40 लाख लोगों को लाभ पहुंचा है। जन औषधि केन्द्रों से भी लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राजग सरकार में बिहार लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, एएनएम इंस्टीट्यूट हर जिले में खोले जा रहे हैं। हाई लेवल एक्सीलेंस सेंटर्स भी खुले हैं। सोलर ड्रोन टेक्नोलॉजी से ऑप्टिकल फाइबर मेन्युफेक्चरिंग हो रही है। स्थानीय भाषा में पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्थापना की जा रही है। 30 अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। न्यू इथेनॉल मेन्युफेक्चरिंग पॉलिसी पर बल दिया जा रहा है, जिस पर अगले चार साल में लगभग 12,000 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। मुख्यमंत्री बालक-बालिका प्रोत्साहन योजना से ड्रॉप-आउट रेशियो में सुधार हुआ है और लिट्रेसी रेट बढ़ा है। ■

'तृणमूल कांग्रेस के अत्याचार को जनता के सामने उजागर करना चाहिए'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 29 जून, 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित किया।

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर बोलते हुए श्री नड्डा ने कहा कि टीएमसी ने विधान सभा चुनाव में विजय मनाने से पहले ही विध्वंस की राजनीति शुरू की। बंगाल विधान सभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में 1,399 प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया गया, 1298 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की गई, 676 लूट की घटनायें हुई और कम से कम 108 परिवारों को धमकाया गया।

श्री नड्डा ने कहा कि बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस में कमीशन ने 2,067 शिकायत दर्ज की है, ह्यूमन राइट्स कमिटी में 254, एससी कमीशन में 1769, एसटी कमीशन में 25, वूमेन कमीशन में 19 और जनरल पुलिस कम्प्लेंट के रूप में 5,650 केस दर्ज हुए हैं। आरामबाग और बिष्णुपुर के भाजपा कार्यालयों को जला दिया गया। ममता बनर्जी जी के रूप में एक महिला मुख्यमंत्री के रहते पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किया गया। हमें इस तथ्य को जनता के सामने उजागर करना चाहिए।

वैक्सीनेशन अभियान को पटरी से उतारने के लिए ममता बनर्जी के बयानों को लेकर उन पर हमला करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारत में कल तक लगभग 32.38 करोड़ डोज एडमिनिस्टर किये जा चुके हैं जो विश्व में सर्वाधिक है। ऑल टाइम लो अर्थात् सबसे कम वैक्सीनेशन कहीं हो रहा है तो वह पश्चिम बंगाल में हो रहा है।

देश में वैक्सीन लगाने में घोटाला हुआ तो पश्चिम बंगाल में हुआ और ऐसा घोटाला हुआ कि इनकी ही सांसद को फेक वैक्सीन लगा दिया गया। अरे लगाओगे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय? ममता दीदी, भ्रष्टाचारियों का साथ दोगे तो आपके सांसदों को भी जाली इंजेक्शन ही लगेगा।

श्री नड्डा ने कहा कि मुझे बहुत खुशी के साथ कहना पड़ता है कि आपके सामने ममता दीदी को झुकना पड़ा है और आज हम पश्चिम बंगाल के 72 लाख किसानों में से 20 लाख किसानों को हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आठवीं क़िस्त के दो-दो हजार रुपये दे सके हैं। यह सफलता भारतीय जनता पार्टी की है जिसके आगे तृणमूल कांग्रेस को झुकना पड़ा है, क्योंकि वह किसानों को इस लाभ से वंचित रखना चाहती थीं। ■

'भाजपा सरकार ने असम को विकास-पथ पर अग्रसर किया'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 29 जून, 2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से असम प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया। कार्यक्रम में नवनियुक्त असम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री भावेश कलिता, असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्व सरमा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री रणजीत कुमार दास, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं असम प्रदेश के प्रभारी श्री बैजयंत पांडा, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दिलीप सैकिया, केंद्रीय मंत्री श्री रामेश्वर तेली, राज्य सभा सांसद श्री कामख्या प्रसाद तासा और कार्यसमिति के सभी सदस्य वर्चुअली उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि असम में भाजपा की सरकार आने के पहले कांग्रेस के 15 साल की सरकार में जिस तरह संप्रदायवाद, अलगाववाद और क्षेत्रवाद की ओछी राजनीति हुई और भ्रष्टाचार का जो खेल हुआ, उससे असम को निकाल कर विकास के पथ पर अग्रसर करने का कार्य भाजपा की सरकार ने किया।

उन्होंने कहा कि कोरोना से उपजी समस्याओं से जनता को राहत पहुंचाने के लिए पिछले वर्ष की ही भांति इस वर्ष भी अप्रैल से नवंबर तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। आगामी 10 जुलाई से हमें इस कार्यक्रम से भी जुड़ना है। हमारे कार्यकर्ता पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ें। 20 लाख करोड़ रुपये की निधि से आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू हुई और देश के अर्थचक्र को गतिशील किया गया।

श्री नड्डा ने कहा कि हमारी असम सरकार ने नाम घर और मंदिरों को अतिक्रमण से मुक्त कर, उनका पुनर्निर्माण कर एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठाया है। 188 करोड़ रुपये की लागत से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का काम चल रहा है। राई मोना नेशनल पार्क, देहिंग और पटकाई नेशनल पार्कों का निर्माण किया गया है। फोरेस्ट स्टाफ के राशन एमाउंट को बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। अरुणोदोई योजना के तहत लगभग 17 लाख मार्जिनल फैमिली की इनकम को बढ़ाया गया है। ■

भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 28 जून, 2021 को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। घोषित उपायों का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए तैयार करना और विकास एवं रोज़गार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।

6,28,993 करोड़ रुपयों की राशि के कुल 17 उपायों की घोषणा की गई। इनमें पहले घोषित किए गए दो उपाय, डीएपी और पीएंडके उर्वरकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी और मई से नवंबर, 2021 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कई ट्वीट्स के माध्यम से कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित उपायों से विशेष रूप से सेवाओं की कमी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, चिकित्सा अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और महत्वपूर्ण मानव संसाधन में बढ़ोतरी होगी। इसमें हमारे बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया है।

राहत पैकेज से विशेष रूप से सेवाओं की कमी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, चिकित्सा अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और महत्वपूर्ण मानव संसाधन में बढ़ोतरी होगी

उन्होंने कहा कि हमारे किसानों को सहायता देने को महत्व दिया गया है। ऐसी कई पहलों का ऐलान किया गया है, जिससे उनकी लागत घटती है, उनकी आय बढ़ती है और कृषि गतिविधियों में लचीलेपन व स्थायित्व को समर्थन मिलता है।

श्री मोदी ने कहा कि हमारे छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार में लगे लोगों को उनकी कारोबारी गतिविधियों को सुचारू रखने और उनके विस्तार में सक्षम बनाने के लिए सहायता का ऐलान किया गया है। इन उपायों से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा व रोजगार सृजन होगा। परिणाम संबद्ध बिजली वितरण योजना और पीपीपी परियोजनाओं व संपत्ति मुद्रीकरण के लिए व्यवस्थित प्रक्रियाओं से हमारी सरकार की सुधारों के लिए जारी प्रतिबद्धता का पता चलता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने तथा लोगों को जरूरी राहत पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के मुख्य बिंदु निम्न हैं:

- कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए गए
- 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटकों/गाइड/यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता
- पहले 5 लाख पर्यटकों को एक महीने का निःशुल्क पर्यटक वीज़ा
- 31 मार्च, 2022 तक 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' का विस्तार

25 लाख व्यक्तियों को ऋण की सुविधा

- क्रेडिट गारंटी योजना के तहत लघु वित्त संस्थानों (एमएफआई) के माध्यम से 25 लाख व्यक्तियों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी
- डीएपी और पीएंडके उर्वरकों के लिए 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार- मई से नवंबर, 2021 तक निःशुल्क खाद्यान्न
- पोषण के लिए जैव-दृढ़ीकृत फसल की 21 प्रजातियां, जलवायु

शेष पृष्ठ 16 पर...

वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 95 अरब डॉलर का सर्वाधिक निर्यात

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 2 जुलाई को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत के इतिहास में 2021-22 की पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक 95 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया। यह 2020-21 की पहली तिमाही के निर्यात से 85 फीसदी और 2019-20 की पहली तिमाही के निर्यात से 18 फीसदी अधिक है। जो कि वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में हुए पिछले अधिकतम निर्यात (82 अरब अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 16 फीसदी अधिक है और 2020-21 की चौथी तिमाही (90 अरब अमेरिकी डॉलर) के अधिकतम निर्यात के रिकॉर्ड से भी ज्यादा है।

ज्यादा श्रमिक आधारित कई क्षेत्रों के निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इंजीनियरिंग उत्पाद क्षेत्र में निर्यात 2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में 5.2 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़ा है। इसी तरह चावल के निर्यात में मई, 2020 से लगातार बढ़ोतरी बनी हुई है और 2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में 2021-22 की पहली तिमाही में 37 फीसदी बढ़ोतरी हुई है।

भारत ने दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अप्रैल, 2020 में निर्यात क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था। अप्रैल, 2019 की तुलना में अप्रैल, 2021 के दौरान भारत के निर्यात में बढ़ोतरी, यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका, कोरिया गणराज्य और यूनाइटेड किंगडम जैसी अन्य प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक थी।

रिकॉर्ड एफडीआई प्रवाह

भारत में 2020-21 में 81.72 अरब अमरीकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक एफडीआई प्रवाह हुआ। यह 2019-20 में प्राप्त 74.39 अरब अमरीकी डालर की तुलना में 10 फीसदी अधिक है। अप्रैल, 2021 के दौरान 6.24 अरब अमरीकी डालर के एफडीआई प्रवाह के साथ लगातार बढ़ोतरी जारी है, जो अप्रैल, 2020 की तुलना में 38 फीसदी अधिक है।

स्टार्टअप इंडिया

डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई और यह स्टार्ट अप भारत के 623 जिलों में मौजूद हैं। वर्ष 2020-21 में 16,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के जरिए लगभग 1.8 लाख औपचारिक नौकरियां पैदा हुई। स्टार्टअप इकोसिस्टम से कई गुना ज्यादा लाभ पहुंचा है।

बिजनेस करना आसान करने और कंप्लायंस बोझ को कम करने के लिए पहले चरण में 6,426 कंप्लायंस कम किए गए। दूसरे चरण में 3,177 कंप्लायंस कम किए जा रहे हैं। पहले चरण की समय सीमा 31 मार्च, 2021 थी और दूसरे चरण की समय सीमा 15 अगस्त, 2021 है।

इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल

क्लीयरेंस और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एकीकरण के पहले चरण में 43 विभागों/मंत्रालयों और 14 राज्यों के एकल खिड़की प्रणाली को शामिल किया जा रहा है। ■

पृष्ठ 15 का शेष...

की पूर्व स्थिति और अन्य विशिष्टताएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी

- 77.45 करोड़ रुपये के पैकेज के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) का पुनरुद्धार

बच्चों पर विशेष ध्यान

- बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल/बाल चिकित्सा बिस्तरों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त 23,220 करोड़ रुपये प्रदान किए
- राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन
- निर्यात बीमा कवर के लिए 88,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन
- 2025-26 तक बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के कार्यकाल का विस्तार

प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा

- भारतनेट पीपीपी मॉडल के तहत प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान करने के लिए 19,041 करोड़ रुपये प्रदान किए
- सुधार आधारित परिणाम से जुड़ी ऊर्जा वितरण योजना के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये
- सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजनाओं और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया ■

जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ: नरेन्द्र मोदी

जीएसटी के 4 वर्ष पूरे होने पर प्रधाननमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी सराहना की। उन्होंने 30 जून को कहा कि यह भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसने करों की संख्या, अनुपालन बोझ और आम आदमी पर समग्र कर बोझ में कमी की है जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और समग्र संग्रह में काफी वृद्धि हुई है।

गौरतलब है कि जीएसटी 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया एक ऐतिहासिक कर सुधार है। पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी की दरों में कमी आई है, प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ है और बढ़ती अर्थव्यवस्था ने भी कर आधार में बड़ी तेजी से वृद्धि की है। जीएसटी राजस्व में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है और यह लगातार आठ महीनों से 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से ज्यादा रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार जीएसटी के 4 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर उन करदाताओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया, जो जीएसटी की सफलता की गाथा का हिस्सा रहे हैं। अतः इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा उन करदाताओं की पहचान करने के लिए डेटा विश्लेषण किया गया, जिन्होंने समय पर रिटर्न दाखिल करने के साथ-साथ नकद में जीएसटी के भुगतान में व्यापक योगदान किया है। इसके परिणामस्वरूप 54,439 करदाताओं की पहचान की गई। इनमें से 88% से भी अधिक करदाता सूक्ष्म (36%), लघु (41%) और मध्यम उद्यमों (11%) से जुड़े हुए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में जीएसटी की दरों में कमी आई है, प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ है और बढ़ती अर्थव्यवस्था ने भी कर आधार में बड़ी तेजी से वृद्धि की है। जीएसटी राजस्व में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है और यह लगातार आठ महीनों से 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से ज्यादा रहा है

वैसे तो यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि राष्ट्र लाखों ईमानदार करदाताओं द्वारा किए जाने वाले कर भुगतान के जरिए जुटाए गए राजस्व से ही विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों एवं कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास पर खर्च करने संबंधी अपने दायित्वों को पूरा करता है, लेकिन यह कदम सरकार द्वारा जीएसटी करदाताओं के योगदान के लिए उनसे सीधे संवाद करने का पहला प्रयास है।

इसकी विशिष्ट सराहना किए जाने के रूप में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड इन करदाताओं को प्रशंसा प्रमाणपत्र जारी करेगा। वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) विभिन्न करदाताओं को प्रशंसा प्रमाणपत्र ई-मेल द्वारा भेजेगा। करदाता इन प्रमाणपत्रों को प्रिंट और प्रदर्शित कर सकेंगे।

केंद्र सरकार करदाता सेवाओं में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और सभी करदाताओं की ओर से स्वैच्छिक अनुपालन और एक मजबूत एवं सुदृढ़ भारत के लिए राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए उनका सहयोग चाहती है। ■

कर्ज गारंटी योजना और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के विस्तार को मिली स्वीकृति

गत 30 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 की दूसरी लहर से विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में आई बाधाओं को देखते हुए स्वास्थ्य/चिकित्सा अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं के विस्तार (ब्राउनफील्ड) और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को वित्तीय गारंटी कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ के वित्तपोषण में सक्षम बनाने के लिए कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) को स्वीकृति दे दी।

मंत्रिमंडल ने बेहतर स्वास्थ्य से संबद्ध अन्य क्षेत्रों/ऋणदाताओं के लिए एक योजना शुरू करने को भी स्वीकृति दे दी। बदलते हालात के आधार पर विस्तृत तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 1,50,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्तपोषण को भी स्वीकृति दे दी।

लक्ष्य

एलजीएससीएएस: यह योजना 31 मार्च, 2022 तक स्वीकृत सभी पात्र कर्जों या 50,000 करोड़ रुपये तक स्वीकृत धनराशि तक, जो भी पहले हो, पर लागू होगी।

ईसीएलजीएस: यह लगातार जारी रहने वाली योजना है। योजना 30 सितम्बर, 2021 तक गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) के तहत या जीईसीएल के तहत चार लाख 50 हजार करोड़ रुपये की धनराशि तक स्वीकृत कर्जों, जो भी पहले हो, पर लागू होगी। ■

चिति

दीनदयाल उपाध्याय

किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व उसकी चिति के कारण होता है। चिति के ही उदयावपात होता है। भारतीय राष्ट्र के भी उत्थान और पतन का वास्तविक कारण हमारी चिति का प्रकाश अथवा उसका अभाव है। आज भारत उन्नति की आकांक्षा कर रहा है। संसार में बलशाली एवं वैभवशाली राष्ट्र के नाते खड़ा होना चाहता है। चारों ओर लोग इस ध्येय का उच्चारण कर रहे हैं तथा उसके लिए प्रयत्नशील भी हैं। ऐसी दशा में हमको अपनी चिति का ज्ञान करना आवश्यक है। बिना चिति के ज्ञान के प्रथम तो हमारे प्रयत्नों में प्रेरक शक्ति का अभाव रहने के कारण वे फलीभूत नहीं होंगे; द्वितीय मन में भारत के कल्याण की इच्छा रखकर और उसके लिए जी तोड़ परिश्रम करके भी हम भारत को भव्य बनाने के स्थान पर उसको नष्ट कर देंगे। स्वप्रकृति के प्रतिकूल किए हुए कार्य के परिणामस्वरूप जीवन में जो परिवर्तन दिखाई देता है, वह विकास के स्थान पर विनाश का द्योतक है और इस प्रकार 'विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम' की उक्ति चरितार्थ होती है।

किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व उसकी चिति के कारण होता है। चिति के ही उदयावपात होता है। भारतीय राष्ट्र के भी उत्थान और पतन का वास्तविक कारण हमारी चिति का प्रकाश अथवा उसका अभाव है

हमारे राष्ट्र जीवन की चिति क्या है? हमारी आत्मा का क्या स्वरूप है? इस स्वरूप की व्याख्या करना कठिन है; उसका तो साक्षात्कार ही संभव है, किंतु जिन महापुरुषों ने राष्ट्रात्मा का पूर्ण साक्षात्कार किया, जिनके जीवन में चिति का प्रकाश उज्ज्वलतम रहा है उनके जीवन की ओर देखने से, उनके जीवन की क्रियाओं और घटनाओं का विश्लेषण करने से, हम अपनी चिति के स्वरूप की कुछ झलक पा सकते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक चली आनेवाली राष्ट्र पुरुषों की परंपरा के भीतर छिपे हुए सूत्र को यदि हम ढूंढ़े तो संभवतया चिति के व्यक्त परिणाम की मीमांसा से उसके अव्यक्त कारण की भी हमको अनुभूति हो सके। जिन महान् विभूतियों के नाम स्मरण मात्र से हम अपने जीवन में दुर्बलता के क्षणों में शक्ति का अनुभव करते हैं, कायरता की कृति का स्थान वीर व्रत ले लेता है, उनके जीवन में कौन सी बात है, जो हममें इतना सामर्थ्य भर देती है? कौन सी चीज है जिसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं? हमारा मस्तक श्रद्धा से किसके सामने नत होता है और क्यों?

वह कौन सा लक्ष्य है जिसके चारों ओर हमारा राष्ट्र जीवन घूमता आया है? अपने राष्ट्र के किस तत्त्व को बचाने के लिए हमने बड़े-बड़े युद्ध किए? किसके लिए लाखों का बलिदान हुआ? उत्तर हो सकता है भारत की भूमि के लिए। किंतु भारत से तात्पर्य क्या जड़ भूमि से है? क्या हमने हिमालय के पत्थर और गंगा के जल की रक्षा की है? हमारे अवतारों ने किस हेतु जन्म लिया था? उनको हम भगवान् का अवतार क्यों कहते हैं?

उपर्युक्त अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का यदि हम उत्तर दें तो हमको अपनी चिति का पता चल सकता है। हमारे शास्त्रकारों ने इसको 'धर्म' के नाम से पुकारा है। आज धर्म शब्द के भ्रमपूर्ण अर्थ प्रचलित हो गए हैं। अंग्रेजी के 'रिलीजन' का पर्यायवाची मानकर तथा 'रिलीजन' और 'दीन' के नाम पर यूरोप तथा अन्य देशों में जो-जो अमानुषिक अत्याचार हुए हैं उनका संबंध इसके साथ बैठाकर, लोग धर्म शब्द से चिढ़ने लग गए हैं। वे धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं अथवा उनमें जो नरम दल के हैं वे धर्म को केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित चाहते हैं। राष्ट्र और समाज का धर्म से वे कोई संबंध नहीं मानते। जहां तक 'धर्म' से उनका तात्पर्य रिलीजन से है, वे सही हो सकते हैं। किंतु धर्म का अर्थ तो व्यापक है और इस व्यापक अर्थ के पीछे जो भाव हैं वे ही भाव भारत की कोटि-कोटि जनता में धर्म शब्द को सुनकर उत्पन्न होते हैं। आज राम और कृष्ण हमारे धर्म के महापुरुष कहे जाते हैं। क्या वे किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है? कौन सा राष्ट्र भक्त उनकी स्मृति को भारत से मिटा देना चाहेगा? रामायण और महाभारत हमारे धर्म ग्रंथ हैं। क्या वे हमारे लिए अपठनीय हैं? क्या उनमें आज के राष्ट्र जीवन को प्रेरणा देनेवाला कुछ भी नहीं है? हमारा धर्म हमको गंगा को पवित्र मानना सिखाता है, हमारा धर्म हमको चारों धाम की यात्रा द्वारा भारतभूमि की परिक्रमा करने को कहता है। क्या यह राष्ट्र भक्ति की उज्ज्वलतम भावना ही नहीं है?

हमारा धर्म हमारे राष्ट्र की आत्मा है। बिना धर्म के राष्ट्र जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। भारतीय राष्ट्र न तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए भू-खंड से बन सकता है और न तीस करोड़ मनुष्यों के झुंड से। एक ऐसा सूत्र चाहिए जो तीस करोड़ को एक-दूसरे से बांध सके, जो तीस कोटि को इस भूमि में बांध सके। वह सूत्र हमारा धर्म ही है बिना धर्म के भारतीय जीवन का चैतन्य ही नष्ट हो जाएगा, उसकी प्रेरक शक्ति ही जाती रहेगी। अपनी धार्मिक

विशेषता के कारण ही संसार के भिन्न-भिन्न जन समूहों में हम भी राष्ट्र के नाते खड़े हो सकते हैं। धर्म के पैमाने से ही हमने सबको नापा है। धर्म की कसौटी पर ही कसकर हमने खरे-खोटे की जांच की है। हमने किसी को महापुरुष मानकर पूजा है तो इसलिए कि उनके जीवन में पग-पग हमको धार्मिकता दृष्टिगोचर होती है। राम हमारे आराध्य देव बनकर रहे हैं और रावण सदा से घृणा का पात्र बना है। क्यों? राम धर्म के रक्षक थे और रावण धर्म का विनाश करना चाहता था। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों भाई-भाई थे, दोनों राज्य चाहते थे, एक के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है तो दूसरे के प्रति घृणा।

केवल धर्म के भाव अथवा अभाव के कारण ही एक स्थान पर एक को बुरा मानते हैं तो दूसरे स्थान पर उसीको अच्छा कहते हैं। इसीके लिए देशद्रोही विभीषण परम वैष्णव हुआ और सुई के बराबर भी भूमि न देने को तैयार दुर्योधन विष्णुद्रोही गिना गया। एक ओर राजभक्ति को हमने माना है तो धर्म के लिए ही ऋषियों ने वेन को राज्यच्युत किया था। धर्म के लिए ही श्रवणकुमार अपने माता-पिता को कंधे पर लिए-लिए घूमा, धर्म के लिए ही प्रह्लाद ने हिरण्यकश्यप का विरोध किया। राम ने एक पत्नी-व्रत का पालन करके धर्म की रक्षा की तो कृष्ण ने अनेकों विवाह करके उसी धर्म को निभाया। अपने इतिहास में अनेक ऐसे श्रद्धास्पद उदाहरण मिलेंगे जिनमें इस प्रकार का विरोधाभास होगा, उनकी निराकृति केवल धर्म के भाव से ही संभव है।

हम अपने जीवन में धर्म को महत्त्व देकर ही प्रत्येक कार्य करते हैं। हमारा उठना-बैठना, सोना, खाना-पीना सबके पीछे धर्म का भाव रहता है। इसलिए स्मृति ग्रंथों में उनके संबंध में नियम दिए गए हैं। स्मृति-ग्रंथों को सभी धर्म-ग्रंथ मानते हैं। हमारा साहित्य लोक-कल्याण की धार्मिक भावना से ही प्रेरणा लेता है कवि अपनी रचना 'स्वान्तः सुखाय' करते हुए भी अंतःकरण में आत्मा के साक्षात्कार की अनुभूति में सुख लेता हुआ धार्मिक प्रवृत्ति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। क्या कोई कवि भारत में हुआ है जिसके काव्य के एक-एक पद में राष्ट्रात्मा की पुकार हो और वह धार्मिक भावना से परिपूर्ण न हो। हमारे बाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसी, सूर, ज्ञानदेव, समर्थ, चैतन्य और नानक कवि थे, साथ ही ऋषि और संत भी थे। हमारे धर्म को अपने आचरण में लानेवाले आदर्श महापुरुष थे। इसीलिए उनके शब्द राष्ट्र के शब्द हो गए हैं; उनकी वाणी युग-युग में राष्ट्र जीवन का संचार करती आई है। हमारे राजनीतिज्ञ, आचार्यों ने भी राजनीति पर धर्म का पुट चढ़ाया है। शुक्राचार्य और चाणक्य धर्मविहीन राजनीति के पोषक नहीं थे। धर्महीन राजनीति का कोई अर्थ ही नहीं है। हमारे सम्राटों ने अश्वमेघ यज्ञ धर्म समझकर किए या राजनीति समझकर? राणा प्रताप का अकबर से युद्ध राजनीति के क्षेत्र में आता है या धर्म के क्षेत्र में। शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह राजनीतिक नेता हैं या धार्मिक। दयानंद और विवेकानंद के कार्य का भारत की राजनीति और राष्ट्र पर क्या कोई प्रभाव नहीं है? गांधीजी के भारत व्यापी प्रभाव के पीछे उनका महात्मापन, उनका धार्मिकपन है या राजनीति? स्वदेशी आंदोलन में फांसी के तख्ते पर गीता की प्रति लेकर चढ़नेवाले क्रांतिकारी वीरों में धार्मिक प्रेरणा थी या राजनीतिक? हम देखते हैं कि दोनों को अलग नहीं कर सकते। हमारी राजनीति हमारी धार्मिक वृत्ति का ही परिणाम है, अपनी धार्मिकता की रक्षा करने की एक साधन-मात्र है। यह धार्मिक प्रवृत्ति हमारे राज्य में इतनी व्यापक है कि उससे कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहता। वर्णाश्रम धर्म समाज की एक प्रणाली है किंतु हमने इसको धर्म की वेशभूषा से सुसज्जित किया है। विवाह एक जीवन और समाज की आवश्यकता है, हमने इसको धर्मकृत्य माना है। संतानोत्पत्ति हम धर्म समझकर करते हैं और संतान भी माता-पिता की सेवा धर्म समझकर ही करती है। मरने के बाद श्राद्ध क्रिया भी धर्म मानकर की जाती है। यद्यपि इन सब कार्यों की तह में समाज रचना, जाति की सनातन परंपरा तथा राष्ट्रत्व है। हम नित्य बड़े-बूढ़ों की वंदना करते हैं यह हमारा धर्म है। हम नित्य स्नान करते हैं यह गांव का कोई भी व्यक्ति बताएगा कि उसका धर्म है। इसलिए कर्मकांडी लोग बीमारी की अवस्था तक में स्नान करते हैं। बिना स्नान नहीं रह सकते। बिना स्नान के भोजन न करना धर्म ही है। कुएं पर जूते ले जाना अधर्म है। भोजन की स्वच्छतापूर्वक बनाना धर्म है। अपने-अपने घर में तुलसी हम धर्म समझकर ही रखते हैं, वह मलेरिया नाशक है, यह समझकर नहीं। स्वच्छता और स्वास्थ्य के सभी नियम धर्म बन गए हैं। हमारा कृषक बीज बोता है, उसके पीछे धर्म भावना छिपी है। धर्म भावना के कारण ही, चाहे आज वह विकृत क्यों न हो गई हो, बहुत स्थानों पर ब्राह्मण हल को हाथ नहीं लगाता है। विद्यार्थी गुरु की सेवा करता है, गुरु विद्यार्थी को पुत्रवत् मानता है, इन दोनों के पीछे धर्म की भावना है, की भावना नहीं। जितने ही उदाहरण हम लें सबमें हमें यह दिखाई देगा कि हमारी धार्मिक प्रवृत्ति रही है। जीवन के प्रत्येक कृत्य को हमने धार्मिक रंग में रंगा है और धर्म से प्रेरणा लेकर ही हमने अपने जीवन की रचना की है।

हमारा धर्म हमारे राष्ट्र की आत्मा है। बिना धर्म के राष्ट्र जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। भारतीय राष्ट्र न तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए भू-खंड से बन सकता है और न तीस करोड़ मनुष्यों के झुंड से। एक ऐसा सूत्र चाहिए जो तीस करोड़ को एक-दूसरे से बांध सके, जो तीस कोटि को इस भूमि में बांध सके। वह सूत्र हमारा धर्म ही है

भारत का राष्ट्र जीवन युग-युग में भिन्न-भिन्न स्वरूप में व्यक्त हुआ है किंतु उसके मूल में उसकी धर्म भावना रही है और इसीलिए अनेक विद्वानों ने कहा भी है कि भारत धर्मप्राण देश है। आज अपनी इस आत्मा की प्रेरणा को अचेतन से चेतन के क्षेत्र में लाने पर ही राष्ट्र जीवन में जो विकृति दिखाई देती है, जो विक्षुब्ध, संघर्षमय, अनिश्चितता की अवस्था है, वह दूर की जा सकती है। ■

(राष्ट्रधर्म, कार्तिक पूर्णिमा, वि.सं. २००५, अंक ६)

नहीं रहे भाजपा के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी

उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर से भाजपा के पूर्व सांसद श्री शरद त्रिपाठी का एक जुलाई को निधन हो गया। वह करीब 50 वर्ष के थे। श्री शरद त्रिपाठी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। श्री त्रिपाठी वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव संतकबीर नगर संसदीय क्षेत्र से जीता था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने इस पर गहरा शोक व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि श्री शरद त्रिपाठी के असामयिक निधन ने मुझे और कई अन्य लोगों को दुःखी कर दिया है। उन्हें वंचित लोगों के लिये काम करने और समाज सेवा से प्रेम था। उन्होंने संत कबीर दास जी के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का अभिनव प्रयास किया। उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदनायें।

श्री त्रिपाठी के निधन पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट कर कहा कि संतकबीर नगर के पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी जी के असामयिक निधन से स्तब्ध हूं। उनका जाना उत्तर प्रदेश और भाजपा दोनों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। इस दुःख की घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता

हूं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व सांसद और भाजपा नेता श्री शरद त्रिपाठी के निधन का समाचार बेहद पीड़ादायक है। एक जन प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने हमेशा बड़े प्रभावी तरीक़े से जनता की बात को उठाया। वे सीधे ज़मीन से जुड़कर काम करते थे। उनके निधन से पार्टी ने एक कर्मठ, जुझारू और युवा कार्यकर्ता खो दिया है।

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा के कर्मठ नेता और संतकबीर नगर के पूर्व सांसद श्री शरद त्रिपाठी जी ने हमेशा जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाने का काम किया। उनका असामयिक निधन भाजपा परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। ■

बाबासाहेब के मूल्यों और आदर्शों के अनुसार समाज व राष्ट्र का निर्माण हमारी सच्ची सफलता: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारी सच्ची सफलता बाबासाहेब के मूल्यों और आदर्शों के अनुसार एक समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में है। उन्होंने कहा कि हमने इस दिशा में प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। वे 29 जून, 2021 लखनऊ में डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके बहुमूल्य योगदान से उनकी असाधारण क्षमता और योग्यता का परिचय मिलता है। डॉ. अंबेडकर न केवल एक शिक्षाविद्, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ,

पत्रकार, समाजशास्त्री व समाज सुधारक थे, बल्कि उन्होंने संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्रों में भी अपना अमूल्य योगदान दिया।

बाबासाहेब के आदर्शों को लोकप्रिय बनाएगा डॉ. भीमराव स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आदरणीय डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के आदर्शों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की। श्री मोदी ने 29 जून को एक ट्वीट में कहा कि भारत रत्न डॉ. भीमराव स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र, लखनऊ' युवाओं के बीच आदरणीय डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के आदर्शों को और लोकप्रिय बनाएगा। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस प्रयास में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सराहना करता हूं। ■

'अयोध्या को हमारी बेहतरीन परंपराओं और विकास के सर्वोत्तम परिवर्तन को प्रकट करना चाहिए'

अयोध्या आध्यात्मिक और विशिष्ट दोनों है। इस शहर के मानव लोकाचार का मेल भविष्य के बुनियादी ढांचे के साथ किया जाना चाहिए, जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों सहित सभी के लिए लाभकारी हो

गत 26 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या की विकास योजना की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें अयोध्या के विकास के विभिन्न पहलू शामिल किए गए थे। अयोध्या के विकास की परिकल्पना एक आध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन केंद्र और स्थाई स्मार्ट सिटी के रूप में की जा रही है।

श्री मोदी को अयोध्या से कनेक्टिविटी को सुधारने वाली आगामी और प्रस्तावित अवसंरचना परियोजनाओं से अवगत कराया गया। बैठक में हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन का विस्तार, बस स्टेशन, सड़कें तथा राजमार्गों जैसी विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं के बारे में चर्चा की गई।

आने वाले दिनों में बनाए जाने वाले ग्रीनफील्ड टाउनशिप के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधाएं, आश्रमों, मठों, होटलों और विभिन्न राज्यों के भवनों के लिए जगह शामिल हैं। यहां पर्यटन सहायता केंद्र और विश्वस्तरीय संग्रहालय का भी निर्माण किया जाएगा।

अयोध्या के विकास की परिकल्पना एक आध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन केंद्र और स्थाई स्मार्ट सिटी के रूप में की जा रही है

सरयू नदी और इसके घाटों के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरयू नदीं में परिभ्रमण संचालन (क्रूज ऑपरेशन) नियमित विशेषता होगी। शहर का विकास साइकिल चालकों और पैदल चलने वाले लोगों के लिए पर्याप्त स्थान की स्थिरता सुनिश्चित करके किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए आधुनिक तरीके से यातायात प्रबंधन भी किया जाएगा।

श्री मोदी ने अयोध्या को एक ऐसा शहर बताया जो हर भारतीय की सांस्कृतिक चेतना में अंकित है। उन्होंने कहा कि अयोध्या को हमारी बेहतरीन परंपराओं और हमारे विकासात्मक परिवर्तनों को प्रकट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या आध्यात्मिक और विशिष्ट दोनों है। इस शहर के मानव लोकाचार का मेल भविष्य के बुनियादी ढांचे के साथ किया जाना चाहिए, जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों सहित सभी के लिए लाभकारी हो।

श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों द्वारा उनके जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या की यात्रा करने की इच्छा महसूस होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि निकट भविष्य में अयोध्या में विकास कार्य जारी रहेंगे। इसके साथ ही अयोध्या में प्रगति को नया आयाम देने का समय अब आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारा सामूहिक प्रयास है कि अयोध्या की पहचान का उत्सव मनाया जाए और नवाचारी उपायों के साथ इसकी सांस्कृतिक जीवंतता को बनाए रखा जाए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्रीराम में लोगों को साथ लाने की क्षमता थी, उसी तरह अयोध्या के विकास का काम स्वस्थ जनभागीदारी की भावना से निर्देशित होना चाहिए, विशेषकर युवाओं द्वारा। उन्होंने इस शहर के विकास में प्रतिभाशाली युवाओं के कौशल का लाभ उठाने का आह्वान किया।

बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उप-मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप-मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार के अनेक मंत्री उपस्थित थे। ■

तानाशाही मानसिकता से उपजा था आपातकाल

जिस पार्टी के मूल में लोकतंत्र रचा-बसा न हो, वह भला देश को लोकतंत्र कैसे दे सकती?

अमित शाह
केन्द्रीय गृहमंत्री

आपातकाल को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। भारत का लोकतंत्र मजबूत हो और इस अध्याय की कभी पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की परंपरा का इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीन समय में कई ऐसे राज्य हुए जिनकी शासकीय प्रणाली में प्रजातांत्रिक मूल्यों के आदर्श पढ़ने को मिलते हैं। लिच्छवी, कंबोज सहित मौर्य काल में कलिंग आदि इसमें अग्रणी हैं। कालक्रम में भारत की शासकीय प्रणाली से लोकतांत्रिक मूल्यों का सर्वाधिक क्षय उस बड़े कालखंड में हुआ, जब विदेशी आक्रांताओं के हाथों में भारत के अलग-अलग भूभागों के शासन की बागडोर आई।

नेहरू सरकार ने 'प्रतिबंध' का पहला प्रयोग संघ पर किया, 'पांचजन्य' को किया बैन

आजादी मिलने के बाद भारत आधुनिक लोकतंत्र के रूप में पूर्ण गणराज्य बना। शासन की बागडोर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के हाथों में आई। स्वतंत्रता आंदोलन की कोख से निकली कांग्रेस को स्वाभाविक तौर पर देश की शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। इस दौर में देश के सामने लोकतंत्र के भविष्य और जनता के मौलिक अधिकारों को लेकर अनेक सवाल थे। इन सवालों के जवाब तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों पर आश्रित थे। ये सवाल इसलिए भी खड़े हुए, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या के बाद तथ्यहीन और मिथ्या आरोप के आधार पर नेहरू सरकार ने 'प्रतिबंध' का पहला प्रयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाकर किया। इस कड़ी में 'पांचजन्य' को बैन किया गया। आजाद भारत में किसी पत्र-पत्रिका पर लगा यह पहला 'प्रतिबंध' था। आजाद भारत के लोकतंत्र की यात्रा की शुरुआत में ही ऐसे प्रतिबंध देखे गए।

कांग्रेस ने सत्ता को बचाने के लिए संविधान की मर्यादा को तार-तार कर 1975 में आपातकाल लगा दिया

1951-52 में नेहरू सरकार द्वारा पहला संविधान संशोधन रखा गया, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के प्रश्न पर संसद में विस्तृत चर्चा हुई। भारतीय जनसंघ के नेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में पुरजोर आवाज उठाई थी। इसे विडंबना ही कहेंगे कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन के गर्भ से जन्मी कांग्रेस ने 28 साल लगातार शासन करने के बाद अपनी डगमगाती सत्ता को बचाने के लिए संविधान की मर्यादा को तार-तार करते हुए 1975 में आपातकाल लगा दिया।

25 जून 1975 की आधी रात के बाद पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया

25 जून 1975 की आधी रात के बाद पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया। आम जनता के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी समेत विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। नानाजी देशमुख, जार्ज फर्नांडीज जैसे नेताओं को भूमिगत होना पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई।

भारत के स्वाधीनता आंदोलन के गर्भ से जन्मी कांग्रेस ने 28 साल लगातार शासन करने के बाद अपनी डगमगाती सत्ता को बचाने के लिए संविधान की मर्यादा को तार-तार करते हुए 1975 में आपातकाल लगा दिया

पत्रकारों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया गया

देश यह देखकर अचंभित रह गया कि कैसे इंदिरा गांधी ने निजी सत्ता की महत्वाकांक्षा के आगे संविधान को तिलांजलि दे दी। बिना सरकार की मर्जी के कोई भी मीडिया संस्थान कुछ छाप नहीं सकता था। पत्रकारों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया गया। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सभी मीडिया संस्थान कांग्रेस के मुखपत्र की तरह काम कर रहे थे। इसी संदर्भ में लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि 'मीडिया तो रेंगने लगी, जबकि उसे केवल झुकने को कहा गया था।'

आपातकाल की जड़ें तानाशाही की मानसिकता में होती हैं

अगर हम आपातकाल की जड़ों की तरफ देखें तो इसके पीछे लोकतंत्र विरोधी सोच बड़ा कारण नजर आती है। कुशासन और भ्रष्टाचार से देश भर में उपजा जनांदोलन इंदिरा गांधी के लिए पहले से परेशानी का सबब था। जिन घटनाक्रमों में हाईकोर्ट के आदेश ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद किया, उसे वह स्वीकार नहीं कर पाईं। लोकतंत्र में स्वीकारोक्ति का साहस होना नितांत जरूरी है। मेरा मानना है कि आपातकाल न तो किसी अध्यादेश से आता है और न ही यह किसी घटना के कारण आता है, बल्कि इसकी जड़ें तानाशाही की मानसिकता में होती हैं।

आपातकाल के बीच हुए आम चुनावों में जनता ने कांग्रेस को हार को मुंह दिखाया

आपातकाल के बीच हुए आम चुनावों में जनता ने कांग्रेस को

हार को मुंह दिखाया। इसके बावजूद कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को चुनौती देने की कवायद बंद नहीं की। आज बात-बात पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दिखावटी राग अलापने वाली कांग्रेस पार्टी को राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया 'मानहानि बिल' नहीं भूलना चाहिए। सत्ता के लोभ और अहंकार में कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद के इतिहास में अनेक ऐसे कार्य किए, जो लोकतंत्र की न्यूनतम मर्यादा को खंडित करने वाले हैं।

जिस पार्टी के मूल में लोकतंत्र रचा-बसा न हो, वह पार्टी देश को लोकतंत्र कैसे दे सकती

वास्तव में जिस पार्टी के मूल में लोकतंत्र रचा-बसा न हो, वह पार्टी देश को लोकतंत्र कैसे दे सकती है? दशकों तक लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देकर शासन करने वाली कांग्रेस की संरचना ही वंशवाद की बुनियाद पर टिकी है। यही वंशवाद कांग्रेस की तानाशाही व्यवस्था के मूल में है, जिसकी अनेक उपजों में से एक आपातकाल था।

देश में सशक्त लोकतंत्र भाजपा ही दे सकती है

देश में सशक्त लोकतंत्र वही नेतृत्व एवं राजनीतिक पार्टी दे सकती है, जिसके क्रियाकलाप, आंतरिक बुनावट और कार्यशैली लोकतंत्र की बुनियाद पर आधारित हों। इन सभी मानकों पर भारतीय जनता पार्टी ही शत-प्रतिशत खरी उतरती है। भाजपा की पंचनिष्ठाओं में एक निष्ठा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की इसी भावना को नरेन्द्र मोदी सरकार पिछले सात वर्षों से विभिन्न नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से चरितार्थ कर रही है।

आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब के विचारों के अनुरूप ही लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। भारत के लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि मुझे विश्वास है कि भविष्य में कांग्रेस की तरह कोई भी दल या नेता देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों से खिलवाड़ करके आपातकाल जैसी परिस्थिति उत्पन्न करने का साहस नहीं करेगा

संघीय ढांचे को मजबूती देते हुए राज्यों की भागीदारी को बढ़ाया

जहां एक ओर संघीय ढांचे को मजबूती देते हुए देश में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाया गया, वहीं दूसरी ओर गरीबों को दर्जनों योजनाओं द्वारा देश के विकास की मुख्यधारा में लाया गया। आज लोकतंत्र की सभी इकाइयां एक दूसरे के परस्पर सहयोग, समन्वय तथा संतुलन के साथ चल रही हैं।

मीडिया को अपना काम करने की पूरी आजादी

न्यायपालिका को जहां आवश्यकता दिखाई पड़ती है, वह पूरी स्वतंत्रता के साथ समय-समय पर सरकार का मार्गदर्शन करती रहती है। इसके अतिरिक्त मीडिया को भी अपना काम करने की पूरी आजादी है। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता बताई थी।

पीएम मोदी के नेतृत्व में बाबा साहब के विचारों के अनुरूप ही लोकतंत्र आगे बढ़ रहा

आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब के विचारों के अनुरूप ही लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। भारत के लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि मुझे विश्वास है कि भविष्य में कांग्रेस की तरह कोई भी दल या नेता देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों से खिलवाड़ करके आपातकाल जैसी परिस्थिति उत्पन्न करने का साहस नहीं करेगा। ■

स्वामी विवेकानंद की राष्ट्र-निर्माण संबंधी संकल्पना एवं उसका मार्ग

तरुण चुघ
राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा

यदि आप सहज ही किसी भी छात्र, विद्वान या बुद्धिजीवी से पूछें कि भारतीय जीवन शैली, दर्शन और अध्यात्मवाद का प्रतीक एक अकेला भारतीय व्यक्तित्व कौन है? तो उत्तर होगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लाखों युवाओं को प्रभावित किया है। एक सच्चे कर्मयोगी के रूप में स्वामी विवेकानंद से अधिक किसी अन्य व्यक्ति ने पश्चिमी दुनिया को भारतीय दर्शन से प्रभावित नहीं किया है। वर्ष 1893 के उनके प्रसिद्ध शिकागो (अमेरिका) भाषण ने पश्चिमी दुनिया को भारतीय जीवन और जीवन शैली की ओर उन्मुख किया। यह भारत के लिए एक महान क्षण था, क्योंकि इसने वेदांत-दर्शन में पश्चिम की स्थायी रुचि को जगाया और पुनर्जीवित किया।

स्वामी विवेकानंद का नव-वैदांतिक दर्शन इस प्रश्न से शुरू होता है कि 'मानव-जीवन का उद्देश्य क्या है?' जहां वह बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य है- एक सार्थक, निःस्वार्थ और सेवा-भाव रखने वाला जीवन। उनका विचार है कि जीवन केवल एक अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन है जिसमें दूसरों की मदद करने और उनकी सेवा करने का दृढ़ संकल्प हो। उनके अनुसार, एक सफल जीवन तब तक सार्थक नहीं है, जब तक उसमें दूसरों के लिए सेवा भाव न हो। स्वामी जी के अनुसार, मनुष्य भीतर से तभी विकसित हो सकता है, जब वह बाहर दूसरों को विकसित करे। जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए जो एकांत और सक्रिय जीवन से दूर हो। बल्कि उनका दर्शन एक ऐसे कर्मयोगी का है, जो निःस्वार्थ कर्म से मानवता की सेवा में सक्रिय हो।

स्वामी विवेकानंद का राष्ट्र-निर्माण का मार्ग व्यक्ति-निर्माण से शुरू होता है। उनके अनुसार, राष्ट्रीय चरित्र और कुछ नहीं बल्कि उसके नागरिकों का चरित्र है। अतः राष्ट्र निर्माण का कार्य अपने नागरिकों के व्यक्तित्व-विकास और चरित्र-निर्माण से प्रारंभ होता है। उनके अनुसार, राष्ट्र को महान बनाने के लिए हमें राष्ट्र को महान बनाने वाले नागरिकों को महान बनाना होगा। इसके लिए चरित्र निर्माण जरूरी है। उनके अनुसार, चरित्र में 4 पहलू होते हैं, जो शारीरिक, मानसिक-भावनात्मक, सामाजिक-राष्ट्रीय और आध्यात्मिक हैं।

शारीरिक शक्ति, जिसमें देशवासियों की फिटनेस और स्वास्थ्य शामिल है, को उन्होंने उस आधार के रूप में बताया है, जिस पर मानव-व्यक्तित्व की इमारत टिकी हुई है। उन्होंने कहा, "गीता के अध्ययन की तुलना में आप फुटबॉल के माध्यम से स्वर्ग के अधिक निकट होंगे।"

स्वामी जी के फिटनेस और स्वास्थ्य संबंधी उपरोक्त दर्शन से प्रेरित प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य नागरिकों और युवाओं को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करके स्वस्थ और फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करना है।

उसी तरह योग की प्राचीन भारतीय परंपराओं का अमूल्य उपहार, जो शरीर और मन की एकता का प्रतीक है, से दुनिया को परिचित कराने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'योग दिवस' के माध्यम से किया गया। जिसकी शुरुआत वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र में इस संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए प्रेरक भाषण से हुआ।

शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के अलावा स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि नागरिक बौद्धिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ और रचनात्मक हों। उनके अनुसार, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। यदि मन तीव्र रूप से उनके प्रति उत्सुक है, तो सब कुछ पूरा किया जा सकता है। बड़े-बड़े पहाड़ों को परमाणुओं में तोड़ दिया जा सकता है। उन्होंने कहा- एक विचार आत्मसात करो, उस विचार को व्यक्त करो, उस विचार के बारे में चिंतन करो और उस विचार के अनुसार जीवन जीएं। इस प्रकार उस विचार को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। उस विचार में स्वयं को लीन कर लें। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक न्यूरॉन को उस विचार पर केंद्रित किया जाना चाहिए। आप कर्मयोगी तभी हो सकते हैं, जब आपका मन उन

चुने हुए विचारों के प्रवाह में लीन हो और तभी जीवन की सफलता प्राप्त की जा सकती है।

स्वामी विवेकानंद ने देशवासियों, अधिकारियों और नेताओं के लिए 'राष्ट्र-सेवा' को अपने प्रमुख कर्तव्य के रूप में अपनाने का सुझाव दिया। राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के लिए विवेकानंद का ध्यान युवाओं पर केंद्रित था। वह युवाओं को सलाह देते हैं कि जो कुछ भी उन्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है, उसे जहर के रूप में अस्वीकार कर दें। एक महान राष्ट्र बहादुर एवं साहसी लोगों से बनता है। उनके अनुसार, एक राष्ट्र युवाओं से जो चाहता है, वह है- रक्त में जोश, नसों में ताकत, लोहे जैसी मांसपेशियां और विचारों में नरम। स्वामी जी के अनुसार, यौवन जीवन का सर्वोत्तम समय होता है। जिस तरह से युवा इस अवधि का उपयोग करते हैं, वह उनके आगे आने वाले वर्षों की प्रकृति को तय करता है। उन्होंने कहा, यदि तुम्हे महान कार्य करना है तो किसी भी चीज से मत डरो। जिस क्षण तुम डरोगे, तुम कुछ भी नहीं रहोगे, अस्तित्व विहीन हो जावोगे। भय संसार में दुःख का सबसे बड़ा कारण है। जो कुछ भी करो, उसमें निडर रहो एवं उस पर विश्वास करो। इस बात में विश्वास मत करो कि तुम कमजोर हो, बल्कि तुम खड़े हो जाओ और अपने भीतर की दिव्यता को व्यक्त करो। इसलिए "उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।"

स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर मोदी सरकार ने "मिशन कर्मयोगी (युवा सिविल सेवकों के लिए), स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया मिशन, स्टार्ट-अप इंडिया और ऐसे कई मिशन शुरू किए। मोदी सरकार द्वारा इन सब क्रियाकलापों के माध्यम से राष्ट्र और मानव जाति की सेवा के उद्देश्य के साथ ही साथ राष्ट्र-निर्माण के लिए युवाओं की क्षमता का उपयोग करना है। संस्कृति के उत्थान के लिए एवं बौद्धिक कौशल सीखने और उसे विकसित करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर दिया। उनके लिए शिक्षा केवल तथ्य, आंकड़े और जानकारी नहीं है, बल्कि विचार है। शिक्षा जीवन-निर्माण, मानव-निर्माण, चरित्र-निर्माण के विचारों को आत्मसात करने का साधन है। उनके अनुसार, एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए तथा हमारे देश की संपूर्ण शिक्षा, आध्यात्मिकता और धर्मनिरपेक्षता संबंधी क्रियाकलाप हमारे अपने हाथों में एवं राष्ट्रीय पद्धतियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए।

'नई शिक्षा नीति 2020', वास्तव में स्वामी जी के दर्शन को उन्मुख करती है और मूल्य आधारित शिक्षा इसका लक्ष्य है। जो छात्रों में राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के अंतर्निहित उद्देश्य के साथ, भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास के बारे में जागरूक करने वाली है। 'नई शिक्षा नीति 2020' मूल्य आधारित शिक्षा के साथ ही व्यावहारिक जीवन के सिद्धांत, समृद्ध पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिकता को जोड़ने का भी प्रयास है।

आध्यात्मिक-राष्ट्रवाद

आधुनिक भारतीय-राष्ट्रवाद के पिता के रूप में सम्मानित स्वामी विवेकानंद ने 'आध्यात्मिक-राष्ट्रवाद' के विचार की व्याख्या की। स्वामी जी के अनुसार, राष्ट्रवाद का जड़ अध्यात्मवाद से ही निकलता है। उनके अनुसार, राष्ट्रीय जागृति के लिए धर्म ही मुख्य मार्ग है। उनके लिए धर्म राष्ट्र की नसों का खून है। उन्होंने कहा, "मैं धन्य हूं कि मैंने ऐसे महान हिंदू धर्म में जन्म लिया जो सभी धर्मों को आत्मसात करता है।'' स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारत में धर्म स्थिरता और राष्ट्रीय एकता के लिए एक रचनात्मक शक्ति रहा है। उन्होंने आध्यात्मिकता को भारत के विविध धार्मिक पहचानों के बीच उन्हें एक राष्ट्रीय प्रवाह में एकीकृत करने में सक्षम अभिसरण बिंदु के रूप में देखा। उन्होंने भारतीयों को शक्ति और निडरता का विचार दिया। उन्होंने घोषणा की, 'मेरे धर्म का सार शक्ति है'। उनके लिए पूजा का सबसे अच्छा तरीका था, गरीबों, दलितों, बीमारों और अज्ञानियों में भगवान को देखना और उनकी सेवा करना।

स्वामी विवेकानंद ने देशवासियों, अधिकारियों और नेताओं के लिए 'राष्ट्र-सेवा' को अपने प्रमुख कर्तव्य के रूप में अपनाने का सुझाव दिया

स्वामी जी के अनुसार, राष्ट्रवाद और सार्वभौमिकता शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के दो स्तंभ हैं। लेकिन राष्ट्रवाद संकीर्णता नहीं है और न ही हमारी अपनी सीमाओं तक ही सीमित है। हमारा राष्ट्रवाद सार्वभौमिक शांति के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने कहा, "प्रत्येक राष्ट्र के पास अपने को पूर्ण करने के लिए एक नियति होती है, प्रत्येक राष्ट्र के पास देने के लिए एक संदेश होता है तथा प्रत्येक राष्ट्र को अपने आप को पूर्ण करने का एक मिशन होता है। इसलिए हमें अपनी खुद के मिशन को समझना होगा, इसे किस नियति को पूरा करना है, राष्ट्रों की यात्रा में इसे किस स्थान पर पहुंचना है। इसके लिए आपसी सद्भाव में योगदान देना होगा। मोदी सरकार का 'सबका साथ, सबका विकास' के बाद 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विचार का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद संबंधी आदर्श विचारों के साथ एक आधुनिक और मजबूत भारत बनाना है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सुझाव दिया था, जिसकी भौतिक समृद्धि शिक्षा और मानव-पूंजी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

स्वामी जी ने महसूस किया था कि भारत की ताकत इसके कृषि में निहित है और किसानों की आय में सुधार के लिए उन्होंने कृषि के व्यावसायीकरण का समर्थन किया था। हाल के कृषि सुधार और कृषि-क्षेत्र पर बजट-2021 का फोकस इस तथ्य की गवाही देता है कि मोदी सरकार का जोर भारत के कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर है ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके।

भारत तभी एक विश्व-गुरु हो सकता है जब वह आध्यात्मिकता के मार्ग का अनुसरण करे और उसका राष्ट्रवाद 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत पर आधारित हो। ■

जनसंख्या वृद्धिः समस्या एवं समाधान

शिवप्रकाश
राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, भाजपा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार विश्व जनसंख्या दिवस पर नई जनसंख्या नीति (2021-2030) लेकर आई है। नीति के उद्देश्यों को घोषित करते हुए कहा है कि इस नीति से संसाधनों की आपूर्ति, जनसंख्या विस्फोट में रोकथाम, मूलभूत सुविधाओं रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य का जन सामान्य तक सहज वितरण, लिंग में समानता लाने में सुविधा होगी।

1968 में पॉल आर एहरिच ने अपने शोध पत्र 'The Population Bomb' में जनसंख्या विस्फोट को अनियंत्रित कैंसर के समान बताया है। अधिक जनसंख्या गरीबी, पर्यावरण में क्षरण एवं राजनीतिक अस्थिरता निर्माण करती है। साथ ही साथ बेरोजगारी एवं अपराधों में वृद्धि भी निर्माण करती है।

जनसंख्या नियंत्रण नीति के लागू करने के साथ ही कुछ लोगों के द्वारा विरोध का स्वर भी दिखाई देने लगा। कुछ लोगों ने नीति को विधि के विधान में व्यवधान भी बताया। हम सभी को ज्ञात है कि प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण जो मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है वह भी विधि का विधान ही है। जल, जंगल,जमीन को नष्ट करने से मनुष्य भी नहीं बचेगा। बढ़ती जनसंख्या इन सभी को प्रभावित करती है। आवास के लिए कृषि योग्य भूमि का उपयोग भी धीरे-धीरे कृषि योग्य भूमि को कम कर रहा है।

बेतहाशा वृद्धि के कारण सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सरकारी सुविधाए भी अपर्याप्त होती है। गत दिनों कोरोना महामारी के समय पर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी अपर्याप्त ही थी। ऐसा नहीं है कि ये चुनौती केवल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ही उभरी है। ये चुनौतियां शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं जिसकी वजह से विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रवेश में मारा-मारी से जूझना पड़ता है। बस और ट्रेन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बड़ी आबादी का कितना दबाव बढ़ गया है ये भी किसी से छिपा नहीं है। ये चुनौतियां तेजी से बढ़ती आबादी के मुकाबले बुनियादी ढाचे के विकास में भी हैं।

ऐसा नहीं है कि ज्यादा जनसंख्या से केवल उन्हीं चीजों पर बोझ बढ़ रहा है जो सरकार की तरफ से दी जानी हैं। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो दाना, पानी, ईंधन की चुनौती भी लगातार देश के सामने बड़ी होती जा रही है और यही वजह है कि इन चीजों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है। सामाजिक असमानता का दायरा भी देश में बढ़ता जा रहा है।

प्रत्येक पार्टी चुनाव घोषणा पत्र जारी करते समय रोजगार देने का वायदा करती है, लेकिन बेरोजगार को रोजगार देने में सफल नहीं हो पाती, कारण रोजगार सृजन सीमित है एवं बेरोजगारों की संख्या वृद्धि दोनों का समन्वय ही नहीं हो पाता। जब बेरोजगार व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं पाता तब उसमें से अनेक लोग अपने मार्ग से भटकते हैं एवं अपराध समूह उनका उपयोग करते है। जिससे अपराधों में वृद्धि होती है।

हमें जनसंख्या नीति का समर्थन या विरोध लिंग, भाषा, क्षेत्र अथवा आस्था के आधार पर करने के बजाय समाज हित एवं भविष्य की चुनौतियों को आधार मानकर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति में सहायक तत्वों को प्रोत्साहन एवं अनुपालन न करने वालों को हतोत्साहित करने की व्यवस्था की है

भारत में जनसंख्या विस्फोट की विकराल समस्या को समझने के लिए पहले आकंड़ों पर ध्यान देना होगा। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 17.2 फीसदी रही है। इन्हीं आंकड़ों को अगर वार्षिक वृद्धि समझना है तो इसका जिक्र संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट में मिलता है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से लेकर 2019 के बीच भारत की आबादी की वृद्धि दर 1.2 से बढ़कर 1.36 हो गई है जो चीन के मुकाबले दोगुनी है। इस आंकड़े के मुताबिक 2020 में भारत की आबादी लगभग 138 करोड़ को छू चुकी है।

जनसंख्या नियंत्रण नीति को अनेक लोग आस्थाओं के साथ भी जोड़ कर देखते हैं और समर्थन एवं विरोध इसी आधार पर करते हैं। बढ़ती जनसंख्या का धार्मिक असुंतलन एक वर्ग के लोगों के मन में आशंका भी उत्पन्न करता है। घटनाओं पर संगठित प्रतिक्रिया एवं चुनाव में सामूहिक मतदान इस आशंका को और भी पुष्ट करते हैं। अनेक लोगों को यह भी आशंका है कि असंतुलित जनसंख्या वृद्धि राजनीतिक अस्थिरता एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्था को पंगु बनाएगी।

हमें जनसंख्या नीति का समर्थन या विरोध लिंग, भाषा, क्षेत्र अथवा आस्था के आधार पर करने के बजाय समाज हित एवं भविष्य की चुनौतियों को आधार मानकर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति में सहायक तत्वों को प्रोत्साहन एवं अनुपालन न करने वालों को हतोत्साहित करने की व्यवस्था की है। प्रोत्साहन एवं दंड की व्यवस्था के साथ साथ समाज में जन-जागरण का प्रयास भी करना होगा। समाज की जागरूक संस्थाओं एवं व्यक्तियों को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। ■

'समाज के समुचित मार्गदर्शन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका'

भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं प्रदेश अध्यक्षों की बैठक 1 जुलाई, 2021 को केंद्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने संबोधित किया।

कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा ने कहा कि समाज के समुचित मार्गदर्शन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और भाजपा महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महिला केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे—पोषण योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना इत्यादि को बूथ स्तर तक पंहुचा कर महिला समाज में जागरूकता फ़ैलाने में अथक परिश्रम किया है। कार्यक्रम को भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती वनिथि श्रीनिवासन और मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी श्री दुष्यंत कुमार गौतम ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला मोर्चा की इस बैठक में विभिन्न प्रस्ताव भी पारित हुए।

ऐसे ही एक प्रस्ताव में कहा गया कि किसी देश को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। जब तक महिलाओं को समान अवसर न मिले तब तक कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। इस तथ्य को क्रियान्वित करते हुए मोदी सरकार ने पिछले सात वर्षों में यह सुनिश्चित किया है कि महिलाओं को समान अवसर और भरपूर लाभ दिये जा सके ताकि वो देश के बाकी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हो सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के कल्याण के लिए इतना कुछ किया गया है कि यह काल स्वतंत्र भारत के इतिहास में महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड बन गया है।

प्रस्ताव में आगे कहा गया कि 'न्यू इंडिया' की विकास गाथा को आकार देने में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट किया है कि भारत 'महिला विकास' से 'महिला नेतृत्व वाले विकास' में परिवर्तित हो रहा है। उनकी भव्य दृष्टि में महिलाओं को भारत की प्रगति और विकास के वास्तुकार के रूप में कल्पना की गई है। महिलाओं के 'नेतृत्व वाले विकास' को बढ़ावा देने के लिए पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के निर्माण पर मुख्य ध्यान दिया गया है।

मोदी सरकार में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। 'स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण' के तहत, 2014 में बनाए गए 10 करोड़ से अधिक शौचालयों के साथ 2014 में प्रारंभ हुए

लक्ष्य की उपलब्धि में तेजी से वृद्धि हुई है। जो 2014 में 39 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 100 प्रतिशत हो गया है। इस बुनियादी ढांचे के विकास के प्रभाव की पुष्टि यूनिसेफ द्वारा भी की गई है। मातृ मृत्यु दर में भी 2013 से 2018 के मध्य 35 प्रतिशत की गिरावट आई है। प्रसूता माताओं का स्वास्थ्य एवं कल्याण मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।

महिलाओं की शिक्षा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बालिकाओं की शिक्षा की सुविधा के लिए 'बेटी बचाओ-बेटी पढाओ' कार्यक्रम के अन्तर्गत आरंभ की गई 'सुकन्या समृद्धि योजना' तीन करोड़ से अधिक महत्वाकांक्षी युवा महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा, महिलाओं की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्साहजनक प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए, मोदी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण 2018 में महिलाओं के पीएचडी नामांकन 2013-14 के 40 प्रतिशत के आकड़े से बढ़कर 44 प्रतिशत हुए हैं।

मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह समर्पित सरकार है। जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में बेटियों और बहनों की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सम्पूर्ण योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, गांव-गांव तक पहुंची उज्ज्वला योजना, स्वावलंबन के लिए मुद्रा योजना, बच्चियों के साथ राक्षसी कृत्य करने वाले दुष्कर्मियों को फांसी की सजा का प्रावधान इसके साक्षी हैं। ऐसी अनेक योजनाओं के मूल में करोड़ों महिलाओं बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना मोदी सरकार ने की है। महिला मोर्चा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचे एवं उनका उचित लाभ भी अन्तिम छोर पर खड़ी महिलाओं तक पहुंचे। ■

असम, मणिपुर एवं तमिलनाडु प्रदेश के नए भाजपा अध्यक्ष नियुक्त

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 26 जून को असम एवं मणिपुर तथा 8 जुलाई को तमिलनाडु प्रदेश भाजपा अध्यक्षों की नियुक्ति की। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी श्री अरुण सिंह ने इसकी घोषणा की। भाजपा, असम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री भाबेश कलिता को नियुक्त किया गया। श्री कलिता असम के रांगिया से विधायक हैं। श्रीमती शारदा देवी को मणिपुर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। श्री के. अन्नामलाई को तमिलनाडु प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री अन्नामलाई पूर्व आईपीएस हैं।

कोविड टीकाकरण को गति देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की 300 वैज्ञानिकों, शिक्षकों ने की सराहना

भारत ने 21 जून को इतिहास रचा, जब केंद्र के नवीनतम टीकाकरण चरण की शुरुआत के साथ ही देश भर में 80 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई

जैसा कि भारत में जारी टीकाकरण अभियान में 21 जून, 2021 के बाद गति देखी गयी है, उसको लेकर प्रमुख राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 300 वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने पूरे देश में टीकाकरण अभियान की गति बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना की।

दरअसल, भारत ने 21 जून को इतिहास भी रचा, जब केंद्र के नवीनतम टीकाकरण चरण की शुरुआत के साथ ही देश भर में 80 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई।

नागरिकों से प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में पूर्ण विश्वास रखने की अपील करते हुए 26 जून 2021 को एक हस्ताक्षरित पत्र में 300 शिक्षाविदों ने टीकों के 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने और कोविड-19 पर काबू पाने की दिशा में केंद्र द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की सराहना की।

300 प्रशंसित शिक्षाविदों में आईआईटी, एम्स, आईआईएसईआर, आईसीएमआर संस्थानों, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का मेडिकल सेंटर - यूएसए, कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एनआईपीजीआर, बोस इंस्टीट्यूट, आईसीजीईबी, बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और कई केंद्रीय के शोधकर्ता शामिल हैं। साथ ही, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मणिपाल विश्वविद्यालय, इग्नू, बर्मिंघम विश्वविद्यालय और अन्य प्रमुख संस्थान के लोग भी शामिल हैं। ■

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रदान की गई 38.54 करोड़ से अधिक टीके की खुराकें

केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के सभी नागरिकों के कोविड-19 टीकाकरण अभियान का नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। इस टीकाकरण अभियान को और अधिक टीकों की उपलब्धता, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए वैक्सीन उपलब्धता का पहले से ही अनुमान लगा लेने के माध्यम से बेहतर योजना बनाने और वैक्सीन आपूर्ति की श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने के माध्यम से तेज किया गया है।

देश के सभी नागरिकों के कोविड-19 टीकाकरण अभियान का नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी सहायता कर रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के इस नए चरण में केंद्र सरकार देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75% स्वयं खरीद कर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसकी निःशुल्क आपूर्ति करेगी।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक सभी स्रोतों के माध्यम से 38.54 करोड़ से अधिक वैक्सीन (खुराकें) प्रदान की जा चुकी हैं। इसमें से 10 जुलाई की सुबह 8 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अपव्यय सहित कुल खपत 36 करोड़ 80 लाख 68 हजार 124 खुराक है। एक करोड़ 73 लाख से अधिक (1,73,33,026) बची हुई शेष और अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास उपलब्ध हैं जिन्हें लाभार्थियों को दिया जाना है। ■

प्रधानमंत्री ने इस हफ्ते टीकाकरण की गति में बढ़ोतरी पर संतोष जाहिर किया

गत 26 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में टीकाकरण की प्रगति और कोविड के हालात की समीक्षा के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की। अधिकारियों ने देश में टीकाकरण की प्रगति पर श्री मोदी के सामने एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। प्रधानमंत्री को उम्रवार टीकाकरण के बारे में बताया गया। श्री मोदी को विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य कर्मचारियों, फ्रंटलाइन कर्मचारियों और सामान्य जनसंख्या के टीकाकरण की स्थिति के बारे में भी बताया गया।

अधिकारियों ने आने वाले महीनों में वैक्सीन की आपूर्ति और उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में श्री मोदी को अवगत कराया। प्रधानमंत्री को बताया गया कि पिछले छह दिनों में 3.77 करोड़ डोज लगा दी गई हैं, जो मलेशिया, सऊदी अरब और कनाडा जैसे देशों की कुल आबादी से ज्यादा है।

पिछले 6 दिन में 3.77 करोड़ डोज लगाई गई, जो मलेशिया, सऊदी अरब और कनाडा जैसे देशों की पूरी आबादी से ज्यादा है

इस बात पर भी चर्चा की गई कि देश में 128 जिलों में 45 वर्ष से अधिक उम्र की 50 प्रतिशत से ज्यादा और 16 जिलों में 45 वर्ष से अधिक उम्र की 90 प्रतिशत से ज्यादा आबादी का टीकाकरण कर दिया गया है। श्री मोदी ने इस हफ्ते टीकाकरण की गति में बढ़ोतरी पर संतोष जाहिर किया और इस बात पर जोर दिया कि इस गति को बनाए रखना खासा महत्वपूर्ण है।

अधिकारियों ने श्री मोदी को बताया कि वे टीकाकरण के उद्देश्य से लोगों तक पहुंचने के नए तरीके खोजने और उन्हें लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री ने इन प्रयासों में एनजीओ और अन्य संगठनों को जोड़ने की जरूरत पर बात की।

श्री मोदी ने अधिकारियों को राज्यों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जांच की गति कम न हो, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में संक्रमण में बढ़ोतरी पर नजर रखने और रोक के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण हथियार है।

अधिकारियों ने श्री मोदी को वैश्विक स्तर पर कोविन प्लेटफॉर्म में बढ़ती दिलचस्पी के बारे में भी अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी देशों की सहायता के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, जिन्होंने कोविन प्लेटफॉर्म के रूप में भारत की समृद्ध तकनीक विशेषज्ञता में दिलचस्पी दिखाई है। ■

प्रधानमंत्री को 'द रामायण ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंहजी' की पहली प्रति प्राप्त हुई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को नौ जुलाई को प्रख्यात वकील श्री केटीएस तुलसीजी की मां स्व. श्रीमती बलजीत कौर तुलसीजी द्वारा लिखित पुस्तक 'द रामायण ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंहजी' की पहली प्रति प्राप्त हुई। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे प्रख्यात वकील श्री केटीएस तुलसीजी की मां स्व. श्रीमती बलजीत कौर तुलसीजी द्वारा लिखित पुस्तक 'द रामायण ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंहजी' की पहली प्रति प्राप्त हुई है। यह पुस्तक आईजीएनसीए द्वारा प्रकाशित की गई है। हमारी बातचीत के दौरान विद्वान वकील श्री केटीएस तुलसीजी ने सिख धर्म के महान सिद्धांतों के बारे में बताया और गुरबानी शबद का पाठ भी किया। उनके हाव-भाव ने मेरे मन को छू लिया। ■

स्व. श्रीमती बलजीत कौर तुलसीजी द्वारा लिखित पुस्तक 'द रामायण ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंहजी' की पहली प्रति प्रधानमंत्रीजी को प्राप्त हुई

ऑक्सीजन संयंत्रों के कार्य प्रदर्शन का पता लगाने के लिए आईओटी जैसी उन्नत तकनीकी स्थापित की जाए: नरेन्द्र मोदी

गत नौ जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में ऑक्सीजन उत्पादन में बढ़ोतरी और उपलब्धता में हुई प्रगति की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को देश में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। देशभर में 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की जा रही हैं, जिनमें पीएम केयर्स के योगदान से स्थापित संयंत्रों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्थापित संयंत्र भी शामिल हैं।

पीएम केयर्स के योगदान से स्थापित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र देश के सभी राज्यों और जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। श्री मोदी को यह जानकारी दी गई कि पीएम केयर्स द्वारा स्थापित होने वाले सभी पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र एक बार चालू हो जाएंगे तो 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन युक्त बिस्तर स्थापित किए जा सकेंगे।

उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इन संयंत्रों को जल्द से जल्द चालू किया जाए और इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाए। अधिकारियों ने श्री मोदी को बताया कि वे ऑक्सीजन संयंत्रों को जल्द से जल्द चालू कराने के संबंध में राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऑक्सीजन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के बारे में अस्पताल के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। श्री मोदी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हों। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है और हमारा लक्ष्य देश में लगभग 8000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का है।

श्री मोदी ने यह भी कहा कि हमें स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर इन ऑक्सीजन संयंत्रों के कार्य प्रदर्शन और कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए आईओटी जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी को स्थापित करना चाहिए। अधिकारियों ने उन्हें ऑक्सीजन संयंत्रों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए आईओटी का उपयोग कर रहे एक पायलट के बारे में जानकारी दी।

प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, एमओएचयूए सचिव और अन्य प्रमुख अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। ■

'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 करने को मिली मंजूरी

गत 30 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' (एबीआरवाई) के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को नौ महीने यानी 30 जून, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी। आशा की जाती है कि इस विस्तार के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में अब 71.8 लाख रोजगार पैदा होंगे, जबकि पहले यह आकलन 58.5 लाख रोजगार का था। उल्लेखनीय है कि 18 जून, 2021 तक एबीआरवाई के तहत 79,557 प्रतिष्ठानों के जरिये 21.42 लाख लाभार्थियों को 902 करोड़ रुपये के बराबर के लाभ प्रदान किये गये।

31 मार्च, 2022 तक पंजीकरण की प्रस्तावित बढ़ी हुई अवधि के खर्च को मिलाकर योजना का अनुमानित खर्च 22,098 करोड़ रुपये होगा। इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के जरिये क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि विभिन्न सेक्टरों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम हो और उन्हें ज्यादा से ज्यादा कामगारों को रोजगार देने का प्रोत्साहन मिले।

एबीआरवाई के तहत ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठान और उनके वे नये कामगार, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, उन्हें फायदा पहुंचेगा, बशर्ते प्रतिष्ठान ने नये कामगार रखे हों या जिन कामगारों का रोजगार एक मार्च, 2020 से 30 सितंबर, 2020 के बीच छूट गया हो।

एबीआरवाई के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंश (आय का 24 प्रतिशत) की रकम दो वर्ष तक प्रदान करेगी या कर्मचारियों के अंश (आय का 12 प्रतिशत) प्रदान करेगी। यह ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठान के कुल कर्मचारियों की तादाद पर निर्भर करेगा। योजना की विस्तृत जानकारी को श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा ईपीएफओ की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

गौरतलब है कि 'आत्मनिर्भर भारत 3.0' के तहत अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और कोविड के बाद आर्थिक विकास की गति के दौरान रोजगार पैदा करने के लिये एबीआरवाई की घोषणा की गई थी। यह योजना देश की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के असर को कम करेगी और कम आय वाले मजदूरों की मुश्किलें दूर करेगी। ■

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की भारी जीत

भारतीय जनता पार्टी ने 03 जुलाई, 2021 को आए उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनावों में 75 में से 67 सीटें जीत कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। भाजपा के 21 उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार को निर्विरोध चुना गया। विपक्षी समाजवादी पार्टी ने चुनाव में केवल पांच सीटें जीती, जबकि 2016 में उसने 75 में से 60 सीटें जीती थीं। राष्ट्रीय लोक दल और जनसत्ता दल ने भी एक-एक सीट जीती। एक जिला पंचायत ने निर्दलीय प्रत्याशी को चुना।

विकास, जनसेवा और कानून के शासन के लिए लोगों ने दिया आशीर्वाद: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भाजपा की शानदार जीत विकास, जनसेवा और कानून के शासन के लिए जनता द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी नीतियों को जीत का श्रेय दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम की भी सराहना की।

उत्तर प्रदेश भाजपा के विकास के एजेंडे के साथ है: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने ऐतिहासिक चुनावी जीत के लिए उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं की सराहना की। उन्होंने एक संदेश में उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह और कार्यकर्ताओं को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जिला पंचायत चुनाव के नतीजों से साफ संदेश मिलता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ है। मैं लोगों को भाजपा के प्रति उनके अटूट विश्वास और स्नेह को नमन करता हूं। मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश भाजपा नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं।

जिला पंचायत चुनाव के नतीजों से साफ संदेश मिलता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ है

भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद: योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा उम्मीदवारों ने 75 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों में से 67 पर जीत हासिल की है। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। 2022 का चुनाव भाजपा भारी अंतर से जीतेगी। हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे।

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस जीत की तरह ही पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की सफलता भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी नीतियों और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के कारण है। ■

जल संरक्षण देश सेवा का ही एक रूप है: नरेन्द्र मोदी

अक्सर 'मन की बात' में आपके प्रश्नों की बौछार रहती है। इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, मैं आपसे प्रश्न करूं। तो, ध्यान से सुनिए मेरे सवाल।

.... ओलिंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन था?

.... ओलिंपिक के कौन से खेल में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं?

... ओलिंपिक में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं?

साथियो, आप मुझे जवाब भेजें न भेजें, पर MyGov में ओलिंपिक पर जो क्विज है, उसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कई सारे इनाम जीतेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न MyGov के 'रोड टू टोक्यो क्विज' में हैं। आप 'रोड टू टोक्यो क्विज' में भाग लें। भारत ने पहले कैसा परफॉर्म किया है? हमारी टोक्यो ओलिंपिक के लिए अब क्या तैयारी है?- ये सब ख़ुद जानें और दूसरों को भी बताएं। मैं आप सब से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस क्विज कम्पटीशन में ज़रूर हिस्सा लीजिये।

जब बात टोक्यो ओलिंपिक की हो रही हो, तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे लीजेंडरी एथलिट को कौन भूल सकता है! कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे, तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था।

बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलिंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलिंपिक के लिए टोक्यो जा रहे हैं, तो आपको हमारे एथलिट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है।

जब टैलेंट, डेडिकेशन, डेटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं, तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। हमारे देश में तो अधिकांश खिलाड़ी छोटे-छोटे शहरों, कस्बों, गांवों से निकल करके आते हैं। टोक्यो जा रहे हमारे ओलिंपिक दल में भी कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है।

कोरोना के खिलाफ़ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ़्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया और वो भी एक दिन में! इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ़्त वैक्सीनेशन और वो भी एक दिन में! स्वाभाविक है, इसकी चर्चा भी खूब हुई है।

एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी? आज हम एक दिन में लाखों लोगों को 'मेड इन इंडिया' वैक्सीन मुफ़्त में लगा रहे हैं और यही तो नए भारत की ताक़त है।

वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। कई जगहों पर वैक्सीन हैसिटेनसी को खत्म करने के लिए कई संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग आगे आये हैं और सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

कभी-ना-कभी, ये विश्व के लिए केस स्टडी का विषय बनेगा कि भारत के गांव के लोगों ने, हमारे वनवासी-आदिवासी भाई-बहनों ने, इस कोरोना काल में, किस तरह, अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, स्थानीय ज़रूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाए। गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, खेती का काम भी रुकने नहीं दिया। नजदीक के शहरों में दूध-सब्जियां, ये सब हर रोज पहुंचता रहे, ये भी, गांवों ने सुनिश्चित किया यानी ख़ुद को संभाला, औरों को भी संभाला। ऐसे ही हमें वैक्सीनेशन अभियान में भी करते रहना है।

हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए ही नहीं बरसते, बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकठ्ठा भी होता है, जमीन के जलस्तर को भी सुधारता है। और इसलिए मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूं।

हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सेवा की है। इसलिए, इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे और भी ख़ास हो जाता है।

कोरोना के खिलाफ़ भारत की लड़ाई की एक बड़ी विशेषता है। इस लड़ाई में देश के हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई है। मैंने "मन की बात" में अक्सर इसका ज़िक्र किया है। लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भी रहती है कि उनके बारे में उतनी बात नहीं हो पाती है। अनेक लोग चाहे बैंक स्टाफ हो, टीचर्स हों, छोटे व्यापारी या दुकानदार हों, दुकानों में काम करने वाले लोग हों, रेहड़ी-पटरी वाले भाई-बहन हों, Security वॉचमैन, या फिर पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी- दरअसल यह लिस्ट बहुत ही लंबी है और हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई है। शासन प्रशासन में भी कितने ही लोग अलग-अलग स्तर पर जुटे रहे हैं।

हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए ही नहीं बरसते, बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकठ्ठा भी होता है, जमीन के जलस्तर को भी सुधारता है। और इसलिए मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूं।

आपने संभवतः भारत सरकार में सचिव रहे गुरु प्रसाद महापात्रा जी का नाम सुना होगा। मैं आज "मन की बात" में, उनका ज़िक्र भी करना चाहता हूं। गुरुप्रसाद जी को कोरोना हो गया था, वो अस्पताल में भर्ती थे, और अपना कर्त्तव्य भी निभा रहे थे। देश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़े, दूर-सुदूर इलाकों तक ऑक्सीजन पहुंचे इसके लिए उन्होंने दिन-रात काम किया। एक तरफ कोर्ट कचहरी का चक्कर, मीडिया का प्रेशर - एक साथ कई मोर्चों पर वो लड़ते रहे, बीमारी के दौरान उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। मना करने के बाद भी वो ज़िद करके ऑक्सीजन पर होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हो जाते थे। देशवासियों की इतनी चिंता थी उन्हें। वो अस्पताल के बीएड पर खुद की परवाह किए बिना, देश के लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इंतजाम में जुटे रहे। हम सबके लिए दुखद है कि इस कर्मयोगी को भी देश ने खो दिया है, कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनकी चर्चा कभी हो नहीं पाई। ऐसे हर व्यक्ति को हमारी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं।

आज हमने कोरोना की कठिनाइयों और सावधानियों पर बात की, देश और देशवासियों की कई उपलब्धियों पर भी चर्चा की। अब एक और बड़ा अवसर भी हमारे सामने है। 15 अगस्त भी आने वाला है। आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत-महोत्सव हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम देश के लिए जीना सीखें। आज़ादी की जंग- देश के लिए मरने वालों की कथा है। आज़ादी के बाद के इस समय को हमें देश के लिए जीने वालों की कथा बनाना है। हमारा मंत्र होना चाहिए – इंडिया फर्स्ट। हमारे हर फ़ैसले, हर निर्णय का आधार होना चाहिए - इंडिया फर्स्ट।

अमृत-महोत्सव में देश ने कई सामूहिक लक्ष्य भी तय किए हैं। जैसे, हमें अपने स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हुए उनसे जुड़े इतिहास को पुनर्जीवित करना है। आपको याद होगा कि 'मन की बात' में, मैंने युवाओं से स्वाधीनता संग्राम पर इतिहास लेखन करके, शोध करने, इसकी अपील की थी। मक़सद यह था कि युवा प्रतिभाएं आगे आए, युवा-सोच, युवा-विचार सामने आए, युवा- कलम नई ऊर्जा के साथ लेखन करे। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही कम समय में ढाई हज़ार से ज्यादा युवा इस काम को करने के लिए आगे आए हैं। दिलचस्प बात ये है 19वीं- 20 वीं शताब्दी की जंग की बात तो आमतौर पर होती रहती है लेकिन ख़ुशी इस बात की है कि 21वीं सदी में जो युवक पैदा हुए हैं, 21वीं सदी में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे मेरे नौजवान साथियों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी की आज़ादी की जंग को लोगों के सामने रखने का मोर्चा संभाला है। इन सभी लोगों ने MyGov पर इसका पूरा ब्यौरा भेजा है। ये लोग हिंदी – इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, बांग्ला, तेलुगू, मराठी – मलयालम, गुजराती, ऐसी देश की अलग-अलग भाषाओं में स्वाधीनता संग्राम पर लिखेंगे। कोई स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रहे, अपने आस-पास के स्थानों की जानकारी जुटा रहा है, तो कोई, आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों पर किताब लिख रहा है। एक अच्छी शुरुआत है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अमृत-महोत्सव से जैसे भी जुड़ सकते हैं, ज़रूर जुड़े। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज़ादी के 75 वर्ष के पर्व का साक्षी बन रहे हैं। इसलिए अगली बार जब हम 'मन की बात' में मिलेंगे, तो अमृत-महोत्सव की और तैयारियों पर भी बात करेंगे। आप सब स्वस्थ रहिए, कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़िए, अपने नए-नए प्रयासों से देश को ऐसे ही गति देते रहिए। ■

आठ राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने छह जुलाई, 2021 को आठ राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की। इनमें से 4 राज्यपालों का स्थानांतरण किया गया तथा 4 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये नियुक्तियां संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण किए जाने की तिथि से प्रभावी होंगी। जिन राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए, वे हैं- हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश।

राष्ट्रपति ने निम्नलिखित नियुक्तियां/परिवर्तन किए हैं–

- मिजोरम के राज्यपाल श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई का स्थानांतरण करके गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
- हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य का स्थानांतरण करके त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
- त्रिपुरा के राज्यपाल श्री रमेश बैस का तबादला करके झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
- श्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय का स्थानांतरण करके हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
- डॉ. हरि बाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
- श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
- श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ■

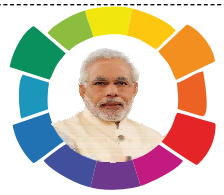

BECOME PART OF A VIBRANT IDEOLOGICAL MOVEMENT
BECOME PROUD MEMBER OF 'KAMAL SANDESH'

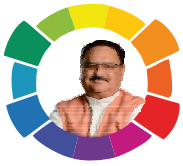

SUBSCRIPTION DETAILS

Name : .....

Address : .....

..... Pin : .....

Phone : ..... Mobile : (1)..... (2).....

E-mail : .....

SUBSCRIPTION TYPE						
	One Year	₹350/-	☐	Life Time (English or Hindi)	₹3000/-	☐
	Three Years	₹1000/-	☐	Life Time (English+Hindi)	₹5000/-	☐

(DETAIL OF THE PAYMENT)

Cheque/Draft No. :..... Date :..... Bank : .....

Note : * DD/Cheque will be made in favour of "**Kamal Sandesh**"
* Money order and Cash accepted with details

(Subscriber's Signature)

KAMAL SANDESH

SEND YOUR DD/CHEQUE ON THIS ADDRESS
Dr. Mookerji Smruti Nyas, PP-66, Subramania Bharati Marg, New Delhi-110003
Ph.: 011-23381428 **Fax:** 011-23387887 **E-mail:** kamalsandesh@yahoo.co.in

KAMAL SANDESH - DEDICATED TO NATIONAL CAUSE

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अयोध्या की विकास योजना की समीक्षा करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

डिजिटल इंडिया अभियान की छठी वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टोक्यो–2020 के लिए भारतीय दल को दी जाने वाली सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए केन्द्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के निदेशकों से बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh @KamalSandesh

kamal.sandesh KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह

डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**

36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953

डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23

Licence to Post without Prepayment

Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह